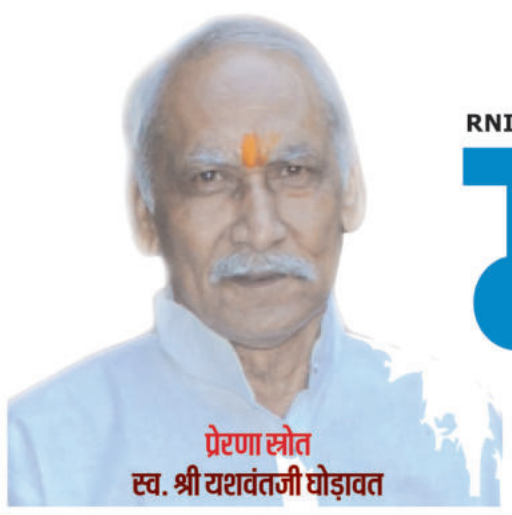

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

योग्यत आपको शीर्ष पर पहुंचा सकती है, लेकिन आपको वहां बनाए रखने के लिए चरित्र की आवश्यकता होती है।

जॉन वुडन

वर्ष-06, अंक - 46 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 08 अगस्त 2024 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

पेरिस ओलंपिक में भारत को नहीं मिलेगा कोई मेडल

विनेश फोगाट फाइनल से अयोग्य

नई दिल्ली।

विनेश फोगाट को फाइनल से पहले अधिक वजन होने के कारण महिला कुश्ती 50 किग्रा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगी और ना ही उनको कोई मेडल मिलेगा। इस बार इस भार वर्ग में सिर्फ गोल्ड मेडल यूएएस की रेस्लर को मिलेगा और कांस्य पदक मैच आयोजित होगा। इस बात की पुष्टि खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने की है। आईओए ने बताया है कि, आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम अधिक था। भारतीय ओलंपिक संघ ने बताया,÷यह खेदजनक है कि, भारतीय दल विनेश फोगाट को महिला कुश्ती 50 किग्रा वर्ग से अयोग्य घोषित करने की खबर साझा करता है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, आज सुबह उनका वजन 50 किग्रा से 100 ग्राम अधिक था। इस समय दल द्वारा कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल आपसे विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वह आने वाली प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा।

बुधवार को एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्योंकि उन्हें महिलाओं की 50 किग्रा स्पर्धा के फाइनल से पहले

अधिक वजन का पाया गया था। विनेश ने मंगलवार रात को इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक के लिए पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया था। आधिकारिक बयान में कहा गया कि बुधवार सुबह उनका वजन अधिक पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

नियम क्या कहता है

यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाएगा।

पीएम मोदी ने लिखा आप चैम्पयिन हैं

पीएम मोदी ने एक्स पर लि?खा विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज की असफलता दुख देती है.।काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता। जो मैं अनुभव कर रहा हूं. साथ ही, मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

अंदर ही अंदर कुछ तो सुलग रहा है, बांग्लादेश जैसे हालात यहां भी हो सकते है!

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। भारत को बांग्लादेश के बिगड़े हालात की चिंता है। वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक विवादित बयान दे दिया है उन्होंने कहा कि, बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि, बांग्लादेश जैसे हिंसक विरोध प्रदर्शन भारत में भी हो सकते हैं, भले ही अभी सब सामान्य दिख रहा है। एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है। उन्होंने कहा कि, हम जीत का जश्न मना रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि, 2024 में जीत बहुत मामूली थी और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। खुर्शीद ने कहा कि सच्चाई यह है कि, अंदर ही अंदर कुछ तो सुलग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि, बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहां भी हो सकता है। हमारा देश इतना बड़ा है कि, बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं हो पाती है। खुर्शीद ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में सीएए-एनआरसी कानून के खिलाफ दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन ने देशभर में इसी तरह के प्रदर्शनों को प्रेरित किया था। सौ दिन तक चले इस आंदोलन को खुर्शीद ने असफल बताया क्योंकि कई लोग अभी भी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि, शाहीन बाग जैसा आंदोलन आज देश में नहीं हो सकता। खुर्शीद ने कहा कि, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं कहूं कि शाहीन बाग विफल रहा? हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि, शाहीन बाग सफल रहा है लेकिन मैं जानता हूं कि शाहीन बाग से जुड़े लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनमें से कितने लोग अभी भी जेल में बंद हैं, उनमें से कितनों को जमानत नहीं मिल पा रही है और कितनों को इस देश का दुश्मन बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद से पूछूं कि क्या शाहीन बाग की पुनरावृत्ति होगी, तो मुझे यकीन नहीं है कि होगी। क्योंकि लोगों ने वास्तव में बहुत कुछ सहा है। बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता है। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ये विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से छात्रों द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर शुरू हुआ था जो अब सरकार विरोधी प्रदर्शनों में तब्दील हो गया है।

ब्रिटेन शरण देने को तैयार नहीं है ऐसे में हसीना की बढ़ सकतीं हैं मुश्किलें

नई दिल्ली, एजेंसी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की लंदन जाने की योजना में अड़चन आ गई है क्योंकि ब्रिटेन उन्हें शरण देने को इच्छुक नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक उनके भारत से बाहर जाने की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद हसीना सी-130जे सैन्य परिवहन विमान से सोमवार को हिंडन एयरबेस पर पहुंचीं। इसके बाद, उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। ब्रिटेन के आव्रजन नियमों के तहत ब्रिटेन के बाहर से शरण के लिए आवेदन करना संभव नहीं है और शरण के प्रत्येक दावे पर मामला-दर-मामला आधार पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाता है। एक विशेषज्ञ ने कहा कि, ब्रिटेन का जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन साथ ही उसके आव्रजन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को शरण या अस्थायी शरण लेने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दी जाए। विशेषज्ञ ने कहा कि, जिन लोगों को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें सबसे पहले सुरक्षित देश में शरण लेनी चाहिए। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि, हसीना ने भारत को अपने संभावित भावी कदमों के बारे में जानकारी दे दी है। यह भी पता चला है कि, हसीना के परिवार के सदस्य फिनलैंड में भी हैं और इसलिए वह उत्तरी यूरोपीय देश जाने के विकल्प पर भी विचार कर रही हैं। सूत्रों ने कहा कि हसीना की यात्रा योजनाओं में कुछ अड़चन आ गई हैं और वह अगले कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। हसीना ने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह विरोध-प्रदर्शन नौकरी में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद यह एक बड़े आंदोलन में बदल गया और हसीना को सत्ता से हटाने की मांग शुरू हो गई थी। हसीना ने लंदन जाने का फैसला इसलिए किया कि, रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटिश संसद की सदस्य हैं। ट्यूलिप वित्त मंत्रालय में आर्थिक सचिव हैं और लेबर पार्टी की सांसद हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सोमवार को लंदन में एक बयान में कहा कि, बांग्लादेश ने पिछले कुछ हफ्तों में अभूतपूर्व हिंसा और जान-माल की हानि देखी है और देश के लोग ''घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार हैं।

मुस्लिम नाबालिग की शादी करना सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

नई दिल्ली,(ईएमएस)। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह एक्ट होने के बाद भी क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग लड़की के निकाह की इजाजत दी जा सकती है? देश की कई अदालतें इस मसले पर अलग-अलग फैसले दे चुकी है। नैशनल कमीशन फॉर प्रोटक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ऐसे ही एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच के सामने रखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सुनवाई करेंगे और इस मामले का निपटारा भी करें। जल्द ही सुनवाई के लिए तारीख भी तय की जाएगी।

2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जावेद के मामले में कहा था कि मुस्लिम लड़की जो नाबालिग है, लेकिन शारीरिक तौर पर वयस्क हो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह कर सकती है। ऐसा ही एक मामला उसी साल केरल हाईकोर्ट में

आया था। तब केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत निकाह चाइल्ड मैरिज (प्रिवेंशन) एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। एनसीपीसीआर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लड़की की उम्र 16 साल है और हाईकोर्ट ने निकाह के पक्ष में फैसला दिया था। एनसीपीसीआर की ओर से तुषार मेहता पेश हुए और सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रोक लगाने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी का असर बाल विवाह पर पड़ सकता है और पॉक्सो एक्ट पर भी असर हो सकता है। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कैसे कोई अनुकरण कर सकता है, जब हम मामला सुन रहे हैं। हम पूरे मुद्दे का परीक्षण करेंगे। 13 जून 2022 को पंजाब हाईकोर्ट का फैसला आया था। कोर्ट के सामने 16 साल की लड़की और 21 साल के लड़के ने याचिका दाखिल कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। कोर्ट को बताया था कि दोनों को प्यार हुआ और 8 जून को उन्होंने शादी कर ली। याचिकाकर्ता ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर दावा किया था कि अगर लड़की प्यूबर्टी यानी शारीरिक रुप से व्यस्क होती है तो वह बालिग मानी जाती है। ऐसे में मर्जी से निकाह करने की हकदार है। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 195 के तहत नाबालिग लड़की प्यूबर्टी पाने के बाद निकाह के लिए योग्य हो जाती है।

एनसीपीसीआर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की और कहा है कि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्नसल लॉ के तहत निकाह की वैधता को गलत तरीके से परिभाषित किया है। हाईकोर्ट ने प्रावधान की गलत व्याख्या की है। वैसे ही नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध चाहे मर्जी से ही क्यों न हो पॉक्सो के तहत अपराध है। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ प्यूबर्टी को निकाह की उम्र मानता है तो भी निकाह की वैधता को जांचा जाना चाहिए और उसे हाईकोर्ट ने नजरअंदाज किया। हाईकोर्ट ने इस बात की गलत व्याख्या की है कि प्यूबर्टी और बालिग होने से निकाह वैध है, क्योंकि पॉक्सो कानून लागू है और मर्जी से भी नाबालिग के साथ संबंध अपराध है। अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने है तो इस मामले में जो कानूनी सवाल उठे हैं उसका जवाब मिलेगा और आगे के लिए एक अहम नजीर बनेगा।

गरीब छात्रों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित, आरटीई लागू करने की अपील

नई दिल्ली।

केंद्र ने बुधवार को राज्य सरकारों से शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को लागू करने की अपील की, जिसके तहत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें अनिवार्य हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा को बताया कि पंजाब, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसी राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों को आरटीई अधिनियम के तहत सीटें आरक्षित करने के लिए आरटीई प्रावधानों को लागू नहीं किया है। आरटीई पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है और सभी के लिए 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा प्रदान करना दोनों का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा आजकल कक्षा 1 में लगभग 100 प्रतिशत नामांकन होता है, यह सभी राज्यों के सामूहिक प्रयासों के कारण है।

हालांकि, प्रधान ने कहा कि जैसे-जैसे कक्षा आगे बढ़ती है संख्या घटती जाती है। उन्होंने कहा कि, यह गिरावट संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों पर निर्भर करती है। प्रधान ने कहा कि हालांकि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, लेकिन स्कूली शिक्षा का ध्यान मुख्य रूप से राज्य सरकारें रखती हैं। उन्होंने कहा आरटीई और एनईपी दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है कि सभी को 12वीं कक्षा तक शिक्षा मिले।

प्रधान ने आगे कहा कि आरटीई, जिसे पिछली सरकार ने बनाया था, में वंचित बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें लाने का अच्छा प्रावधान है।

उन्होंने उन राज्य सरकारों से भी सहयोग की अपील की, जिन्होंने इस प्रावधान को लागू नहीं किया है।

मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, प्रस्तावों को मिली मंजूरी

माही की गूंज, भोपाल।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मे बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।बैठक में लाड़ली बहनों के खाते में 10 तारीख को 1500 रुपए डालने, किसानों के सीमांकन-नामांकन अवधि बढ़ाने, छात्रावास और जेलों में सुधार समेत एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वही रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का त्योहार धूम-धाम से मनाने का भी निर्णय लिया है।

कैबिनेट के अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त और अतिरिक्त राशि पर चर्चा हुई। योजना के तहत 1,29 करोड़ बहनों के खाते में इस महीने की राशि 10 अगस्त को भेजी जाएगी वही लाखों बहनों के खाते में 1250 के साथ राखी का उपहार स्वरूप 250 रुपए डाले जाएंगे। इस तरह लाड़ली बहनों के खाते में 1500 डाले जाएंगे। प्रदेश की लाड़लियों को इस 19 करोड़ की राशि एक क्लिक के माध्यम से दी जाएगी।

किसानों के सीमांकन और नामांकन की अवधि एक महीना बढ़ी।अभी 75 दिन लगते थे, लेकिन जल्द ही साइबर तहसील शुरू होने वाली हैं, जिससे 25 दिन में सीमांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोकतंत्र सेनानियों को मानदेय के साथ

अंतिम संस्कार के लिए 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। उनकी अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ निकाली जाएगी।

कार्य आवंटन की व्यवस्था के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें तकनीकी दक्षता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तकनीक का अधिकतम प्रयोग कर पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया है।

ई-कैबिनेट और ई गवर्नमेंट की अवधारणा को मूर्तरूप देने का निर्णय लिया गया है। यह एक तरह से पेपर लेश व्यवस्था होगी। इसमें कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा।

वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट (पीएमयू) गठित करने और वित्त विभाग में 47 नए पद भी सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

रीवा पालिटेक्निक में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होगी। जेल में बंदियों के कौशल उन्नयन और धार्मिक, आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए चार सौ करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

मैहर, बुरहानपुर में नए जेल बनाए जाएंगे। जुर्माना न चुका पाने कैदियों की मदद की जाएगी। साइबर तहसील चालू करने का फैसला। साइबर तहसील के चालू होते ही 25 से 30 दिन के अंदर समस्याओं का निराकरण होगा। एससी-एसटी और ओबीसी छात्रावासों की सुविधाएं अपग्रेड करने के लिए सरकार ने अफसरों की टीम बनाई है। इसके लिए बजट भी आवंटित किया जाएगा।

9 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रदेश की हर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर झंडा लगाया जाने का निर्णय। 15 अगस्त स्वातंत्रता दिवस को बड़े ही धूम-धाम से मनाने का निर्णय लिया है।

जन्माष्टमी और रक्षाबंधन का पर्व पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से भी कार्यक्रम होंगे।

एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने पर भड़के खड़गे, लगाये आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सदन में एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने पर सवाल उठाया, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को चेतावनी दी और कहा कि, भाजपा और आरएसएस अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान बोलने के लिए खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एनसीईआरटी से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना को हटाया गया है। किताबों में अब तक संविधान की प्रस्तावना छपती आई है। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। ये हमारे संविधान और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को दर्शाता है। खड़गे ने आगे कहा सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे नागरिकों और भावी पीढ़ियों को स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं, संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, मूल्यों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानना ही चाहिए। बीजेपी सरकार ने पराजय के बाद पहले अम्बेडकर जी, गांधी जी की प्रतिमा को हटाया। फिर संविधान से छेड़छाड़ की, लेकिन ऐसे बदलाव जनता स्वीकार नहीं करेगी। आरएसएस-भाजपा अपनी सांप्रदायिक विचारधारा को देश पर थोपने के लिए पाठ्यक्रम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं।

आरडीएसएस में हो रहे भवन व ग्रीड निर्माण कार्य में बरती जा रही लापरवाही

माही की गूंज, खवासा। सुनील सोलंकी

फोटो की एक नजर में ही सामने है भ्रष्टाचार के साथ निम्न व घटिया निर्माण।

ग्रामीण अंचलों में 24 घंटे विद्युत व्यवस्था मिले साथ ही स्मार्ट पद्धति से सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने के उद्देश्य के साथ बिजली वितरण क्षेत्र में बदलाव लाने हैतु जुलाई 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पुनर उत्थान योजना (आरडीएसएस) के तहत जहां ग्रामीण अंचलो मे विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है वहां पर 2025-2026 तक सुचारू बिजली व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें तीव्र गति से कार्य भी किया जा रहा है लेकिन इन होने वाले कार्यों के दौरान लापरवाही भी सामने आ रही है। जिस फर्म व ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है उस ठेकेदार द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है।

कुछ ऐसा ही मामला झाबुआ जिले के ग्रामीण अंचलों मे भी सामने आ रहा है। आरडीएसएस के तहत खवासा क्षेत्र में भी कार्य शुरू किया गया है। बताते हैं पिछले साल ही इसका कार्य शुरू किया गया है। जानकारी अनुसार खवासा विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत सिंचाई व घरेलू एक ही समक्ष लाइट व्यवस्था होने के कारण ग्रामीणों को लाइट सही नहीं मिलने से परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में सिंचाई व घरेलू के लिए एक ही तरह के लाइन मिल रही है। ग्रामीणों को जिसमें कई बार उपभोक्ताओं की शिकायत भी रहती है जिसमे शिकायतों को देखते हुए खवासा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रन्नी,तलावड़ा, कुकड़ीपाड़ा, मकोडिया, सेमलिया, आदि जगह आरडीएसएस के तहत कार्य किया जा रहा है। खवासा ग्रीड़ होने के साथ ही तलावड़ा व सेमलिया मे नए ग्रीड़ का निर्माण किया जा रहा है, जहां नए ग्रीड़ के साथ ही कार्यालय भी विद्युत वितरण का रहेगा। लेकिन तलावडा व सेमलिया में जहां ग्रीड़ का निर्माण हो रहा है वहां बीम-कालम भरने में निम्न व घटिया स्तर की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही झाबुआ मुख्यालय से दुरी अधिक होने से विधुत विभाग के सिविल इंजीनियर या विभागीय अमला भी मौके पर नहीं रहता है व नही नियमित आता है। जिसके कारण ठेकेदार अपनी मनमर्जी अनुसार व निम्न स्तर का नए ग्रीड़ में कार्य कर रहा है जिसे देखने वाला कोई नहीं है।

माही की गूंज प्रतिनिधि ने तलावड़ा व सेमलिया सहित आसपास क्षेत्र में चस्मदित जानकारी ली व देखा तो तलावड़ा व सेमलिया में जिस मान से ग्रीड़ का निर्माण किया जा रहा है वह वाकई में काफी अनियमिता बरती जा रही है। ठेकेदार के कर्मचारी मौके पर रह के कार्य करवा रहे है। न तो वहां समय पर तरी हो पा रही है, कालम में जो माल मटेरियल नियम अनुसार रहना चाहिए वह नहीं दिखाई दे रहा है। तो सीमेंट कम उपयोग में लाई जा रही है और गिट्टी अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है। वही ग्रीड़ का बेस लेवल भी कम में बनाई जा रही है। जिसके कारण आसपास बाउंड्री ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। बताते हैं दो कंपनियां क्षेत्र में आरडीएसएस के तहत कार्य कर रही है। बिड्स कम्पनी बड़वानी की हैं जो सेमलिया ग्रीड़ का निर्माण कर रही है। वही स्पान कंपनी नोएडा (दिल्ली) द्वारा तलावड़ा में ग्रीड़ का निर्माण करवाया जा रहा है। जो ग्रीड़ पर एक विद्युत विभाग का कार्यालय के साथ ग्रीड़ के आसपास बाउंड्री का निर्माण कर रहै। निर्माण में जो सीमेंट-रेत व आदि सामग्री का निम्न स्तर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसे देखने भर में सामने आ रहा है की वह निर्माण कार्य कितने निम्न व घटिया क्वालिटी का है।

मामले में लेबर ठेकेदार प्रकाश नायक(रम्भापुर) से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, आरडीएसएस के तहत स्पान कंपनी नोएडा द्वारा यहा कार्य करवाया जा रहा है। हमने तो पेटी कांट्रेक्टर के रूप में लेबर का काम ले रखा है, साइट पर कंपनी की तरफ से इंजीनियर होगा वह पूरी जानकारी आपको दे देगा, किस स्तर का माल उपयोग लाया जा रहा है इस मामले में, मैं कुछ भी नहीं कह सकता।

वही स्पान कंपनी के धार-झाबुआ प्रभारी सीनियर इंजीनियर रामजी साहू से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, कार्य तो अच्छा चल रहा है आपको जो कमी-पेशी लग रही है उसमें भी सुधार कर दिया जाएगा, खवासा से जूनियर इंजीनियर मुकेश परमार साहब आते हैं उनकी देखरेख में ही कार्य हो रहा है।

मामले में आरडीएसएस के धार-झाबुआ प्रभारी सिविल इंजीनियर संजय नीमा मो. पर 8989983896 माही की गूंज प्रतिनिधि ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।

जयस के बैनर तले दो जगह होंगे आयोजन

आदिवासी दिवस पर भारी भीड़ एक जगह जुटने को लेकर हुआ निर्णय

माही की गूंज, पेटलावद।

सयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त को मनाए जाने वाला विश्व आदिवासी दिवस को लेकर आदिवासी संगठनों ने अपनी और पूरी तैयारियां कर ली है। हर बार की तरह इस बार भी आयोजन में बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है। आयोजन को लेकर जय आदिवासी संगठन (जयस) शुरू से अपने बैनर तले आयोजन करता आ रहा है और लगातार आयोजन के सफल होने के साथ साथ भारी भीड़ जुट रही है। जिसको देखते हुए इस बार संगठन ने आयोजन को दो हिस्सों में बांटते हुए बड़े आयोजन अलग-अलग स्थान पर आयोजित करना तय किया है।

आदिवासी नेता सचिन गामड़ ने बताया कि, इस बार 9 अगस्त पर होने वाले आयोजन दो भागों में बांटा गया है। दोनों आयोजन जयस के बेंनर तले आयोजित होंगे जिंसमे सभी आदिवासी संगठन उपस्थित रहेंगे। इस बार पेटलावद क्षेत्र में दो आयोजन एक पेटलावद शहर में महावीर महाविद्यालय मैदान में जहां पेटलावद, बामनिया, रायपुरिया सहित आसपास के लोग जमा होंगे। जबकि दूसरा आयोजन ग्राम सारंगी में टंट्या मामा की प्रतिमा के पास आयोजित होगा। जिंसमे सारंगी, करवड़ और माही क्षेत्र के युवा और आदिवासी समाज के लोग जमा कर आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाएंगे।

मूल निवासी दिवस और आदिवासी दिवस को लेकर बहस

आदिवासी दिवस को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। आदिवासी समाज मे बने अलग-अलग संगठन इस पर अपनी अलग प्रतिक्रिया दे रहे है। कई संगठन इसे मूल निवासी दिवस बता रहा है। तो जयस सहित उनके सहयोगी संगठन इसे विश्व आदिवासी दिवस जिसे सयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है उसे आदिवासी दिवस के रूप में मना रहे है । हालांकि राजनीति दलों के नेता वोट बैंक के चक्कर मे विचारधारा से अलग भीड़ के हिसाब से आयोजन में शामिल हो जाते है जो बहस का विषय बन जाता है।

मुख्यमंत्री ने की रक्षाबंधन व हर घर तिरंगा अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

माही की गूंज, झाबुआ।

सरकार द्वारा लाड़ली बहना को प्रतिमाह 1250 रूपये राशि के अतिरिक्त रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये राशि अलग से दी जानी है। जिसके लिए प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय क्षेत्रो के वार्डो में रक्षाबंधन एवं श्रावण उत्सव की तर्ज पर आभार सह कार्यक्रम 10 अगस्त को आयोजित किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेसिंग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा निर्देशित किया गया कि, प्रदेश भर में लगभग 25 हजार आयोजन स्थलों पर कार्यक्रम गरिमापूर्ण रूप से सम्पन्न हो। जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जाए। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए रक्षाबन्धन के अवसर पर प्रत्येक लाडली बहना को मुख्यमंत्री का उपहार दिया जा रहा है।

हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम मे हर घर तिरंगा अभियान आव्हान किया गया है। जिसके तहत प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों जैसे तिरंगा रैली, तिरंगा यात्रा, तिरंगा मैराथन, तिरंगा प्रतिज्ञा, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। हर घर तिरंगा अभियान सामाजिक समरसता एवं जनभागीदारी को सुनिश्चित किये जाये एवं प्रत्येक विभागवार दायित्व तय कर तिरंगो की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के पश्चात कलेक्टर नेहा मीना द्वारा निर्देशित किया गया कि, विभागवार अपने दायित्वों को पूर्ण करे साथ ही हर घर तिरंगा अभियान हेतु शेड्यूल तैयार कर प्रत्येक गतिविधियों को किया जाना सुनिश्चित करे।

माही की गूंज, थांदला।

एसपी पद्मविलोचन शुक्ल ने सभी पत्रकारों को देविगढ़ मंदिर पर आमंत्रित किया और भुटटा व भजीया पार्टी कर सभी का परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर पुलिस अधिक्षक शुक्ल ने भांजगड़ी प्रथा के बारे में चर्चा कर विश्वास जताया कि शिक्षा का अभाव होने से यह प्रथा धीरे-धीरे बंद होगी। अंत में पुलिस अधिक्षक ने थांदला के सभी पत्रकारों का आभार माना।

शनि मंदिर पर होगा श्री अखंड रामायण पाठ

माही की गूंज, पेटलावद।

'होई है वहीं जो राम रचि राखा'' के भाव को अपने अंतरमन में समाहीत कर नगर के भक्तों के द्वारा हर वर्ष कई धार्मिक आयोजन किये जाते है। जिसमें नगर के सभी श्रद्वालु माता ,बहन और बंधु हर्ष के साथ भाग ले कर उसे सफल बनाते हुए धार्मिक आयोजन का लाभ लेते है।

ऐसा ही एक आयोजन नगर के शनि मंदिर पर वर्षो से भक्तों के द्वारा किया जाता है। श्री अखंड रामायण पाठ जो की वर्ष में एक बार शनि मंदिर पर होता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में अच्छी वर्षा और नगर सहित आसपास के क्षेत्र की सुख शांति के लिए किया जाता है। यह आयोजन पूर्व में तुलसीदास जी की जयंती पर होता था। किंतु अब इसे समयानुकल देखते हुए किया जाता है।इस बार भी यह आयोजन तुलसीदास जी की जयंती के एक दिन पूर्व प्रारंभ हो कर उस दिन पुर्णाहुति होगी। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शनिमंदिर पर 24 घंटे की श्री अखंड रामायण पाठ का आयोजन रखा जा रहा है। जो की दिनांक 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे प्रारंभ होगा और 11 अगस्त रविवार को महाआरती और यज्ञ के साथ पूर्णाहुति की जाएगी।

कलेक्टर ने स्कूलों के साथ पंचायत व छात्रावास का किया निरीक्षण

माही की गूंज, थांदला।

कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मंगलवार को थांदला प्रवास के दौरान थांदला एसडीएम कोर्ट, शासकीय चिकित्सालय, कस्तुरबा बालिका छात्रावास, सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण किया गया।

थांदला एसडीएम कोर्ट के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नेहा मीना ने भूमि आंवटन के प्रकरणो, 165 के लंबित प्रकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। साथ ही एसडीएम तरुण जैन द्वारा वर्षा काल में जिन रपटों पर पानी आ जाता है उनके चिन्हांकन एवं संकेतक द्वारा राहगीरो को सचेत किये जाने सम्बन्धी कार्यों से अवगत कराया गया। निर्माणाधीन सीएम राइज स्कूल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा समय से कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही संयुक्त दल बनाकर निर्माण की गुणवत्ता सम्बन्धी निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

कस्तुरबा बालिका छात्रावास के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा बालिकाओं को दिए जाने वाले भोजन को स्वयं ने चखा। साथ ही मेन्यु के अनुसार भोजन बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बालिकाओं को स्वयं भोजन एवं खेल समिति बना कर सुपरवाइस करने को प्रोत्साहित किया। हॉस्टल के उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज संख्या का मिलान कर, बालिकाओं के लिए पुस्तकालय एवं न्यूज पेपर की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। शासकीय चिकित्सालय में महिला एवं प्रसुति वार्ड में महिलाओं से स्वास्थ्य एवं टीकाकरण सम्बन्धी दस्तावेजो का निरीक्षण कर अनुपस्थित ड्यूटी डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देश दिए।

पैथोलॉजी के बाहर रक्त संग्रहण हेतु उचित व्यवस्था किए जाने, गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने एवं बैठने की उचित व्यवस्था किए जाने हेतु कहा। साथ ही पोषण पुनर्वास केन्द्र मे एडमिट बच्चों से सम्बन्धी जानकारी ली गयी जिसमे 11 बच्चे एवं 3 रेफर हुए बच्चों की जानकारी प्राप्त हुई। अस्पताल परिसर के सामने पानी की निकासी व्यवस्थित ना होने पर परिसर में पानी एकत्रित होने के कारण सीएमओ थांदला को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

ग्राम पंचायत परवलिया के निरीक्षण के दौरान जन्म-मृत्यु पंजीयन रजिस्टर की जाँच की गयी, पटवारी से फौती नामांकन सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर, आजीविका मिशन के समूह की दीदीयो से चर्चा की गयी। सीईओ थांदला से सुदूर सड़?क का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्माणाधीन बालक छात्रावास के निरीक्षण के दौरान समयानुसार कार्य पूर्ण ना करने पर पीआईयू सब इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित कर, गुणवत्ता हेतु संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। सीडीपीओ थांदला से परवलिया क्षेत्र की समस्त आंगनवाड़ियो का निरीक्षण कर बुधवार तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

आम जनता पर टैक्स की मार, सेवकों पर सरकार मेहरबान

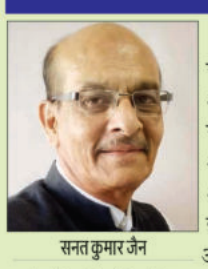

सनत कुमार जैन

पिछले 10 वर्षों से आम जनता के ऊपर लगातार टैक्स और शुल्क बढ़ाए जा रहे हैं। आम जनता की वोट से चुने गए सांसद और विधायकों के वेतन भक्तों और सुविधाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन बढ़ाई जा रही है। सांसद, विधायक और मंत्रियों को क्रीमी लेयर की श्रेणी का सम्मान और धन प्राप्त हो रहा है। उससे अब जनता के बीच में नाराजी देखने को मिल रही है। आम जनता टैक्स की मार से कराह रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद राजनीति में समृद्ध परिवारों के बुजुर्ग अपने बच्चों को राजनीति में नहीं भेजना चाहते थे। उनका मानना था, जनसेवा के लिए घर का पैसा खर्च करेंगे। घर के कामकाज और व्यापार में कोई रुचि नहीं लेंगे। बहुत मुश्किल से लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते थे। उस समय विधायकों और सांसदों को इतना पैसा भी नहीं मिलता था। वह सत्र के समय राजधानी जाकर अपना खर्च पूरा कर सकें। पिछले तीन दशक में स्थितियां बडी तेजी के साथ बदली हैं। विधायकों और सांसदों के वेतन भत्ते लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सांसदों और विधायकों की अप्रत्यक्ष सुविधायें भी बढ़ रही हैं। रेलवे और हवाई जहाज में मुफ्त यात्राएं करने का मौका मिल रहा है। बिजली पानी फ्री मे मिल रहा है। रहने के लिए आवास फ्री मिलता है। कई राज्यों में तो मंत्रियों और विधायकों का आयकर भी सरकार द्वारा भरा जा रहा था। कार्यकाल खत्म होने के बाद पेंशन मिलती है। जितनी बार के विधायक-सांसद उसी के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन आजीवन मिलती है। एक बार चुनाव जीत गए, तो सारे जीवन निशुल्क यात्रा करने की पात्रता हो जाती है। यह सारा खर्च आम जनता द्वारा दिए गए टैक्स से सरकार करती है। जो जनता इन्हें वोट देकर चुनाव जिताती है। उसके बाद जीवन भर उसका बोझ भी उठाती है। पिछले वर्षों में राजनीति भी व्यापार बन गया है। विधायक, सांसद और मंत्रियों के परिवारजन बड़े-बड़े ठेके लेते हैं। उन्हें ही ठेके मिलते हैं। चुनाव जीतने के पहले जिनकी हैसियत चुनाव खर्च उठाने की नहीं होती है। कुछ वर्षों में वह करोड़ों-अरबों रुपए के मालिक वह और उनके परिवार के लोग बन जाते हैं। आम जनता पर लगातार टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। 8 वर्ष पहले जीएसटी कानून लागू किया गया था। इस कानून को लागू करने का उद्देश्य था। अप्रत्यक्ष करों को खत्म करके ऐसी टैक्स व्यवस्था लागू करना,जो सारे देश और सभी राज्यों में एक समान हो। नागरिकों को टैक्स से राहत देने का भरोसा जताया गया था। जीएसटी लागू होने के बाद बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स बंद किए जाने थे। जो केंद्र एवं राज्य सरकारों ने आज तक नहीं किये। उल्टे सेज और सरचार्ज लगाकर आम जनता से जजिया कर की तरह टैक्स वसूल किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल और आयातित सामान सबसे बड़ा उदाहरण है। आम जनता पर टैक्स की दरों को बढ़ाकर 8, 12, 18 और 28 फ़ीसदी कर दिया। 2016 की तुलना में यह डबल हो गया है। गरीब जनता से भी जीएसटी में भारी टैक्स वसूल किया जाने लगा है। जीएसटी कर के दायरे में सेवाओं को भी शामिल किया गया। रेलवे की टिकट हो, बिजली का बिल, नगर निगम का टैक्स, कॉलेज की फीस, बैंक के शुल्क और सरचार्ज इत्यादि का ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा। जो जीएसटी मे कवर ना होता हो। जीएसटी लागू होने के पहले सीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को मात्र चार फ़ीसदी का टैक्स मिलता था। जब से जीएसटी लागू हुआ है। उसके बाद से केंद्र सरकार की कमाई कई गुना बढ़ गई है। वहीं राज्य सरकारों की कमाई जीएसटी लागू होने के बाद घटती चली जा रही है। राज्य सरकारें केंद्र के ऊपर आश्रित होती जा रही हैं। रही सही कसर टोल टैक्स, राज्य सरकारों का सेस, कई गुना लाइसेंस फीस बढ़ाने और जुर्माने के रूप में टैक्सों की वसूली बड़े पैमाने पर की जा रही है। पिछले एक दशक में आम जनता से भारी टैक्स वसूला जा रहा है। जनता टैक्स के बोझ से कराह रही है। आम जनता ने जिन लोगों को वोट देकर चुनाव जिताया। विधायक और सांसद बनाया। वह मौज कर रहे हैं। उनके वेतन भत्ते और सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। गरीब की अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम जनता दो वक्त का पौष्टिक भोजन भी नहीं खा पा रही है। यह पिछले 10 सालों के टेक्स का सत्य है। सामान्य व्यक्ति पर टैक्स की कोई सीमा नहीं है। आम जनता से कई तरह से टैक्स वसूल किया जा रहा है। जिन परिवारों की आय 5 लाख रुपए वार्षिक से कम है। उन्हें अपनी आय का 60 से 65 फ़ीसदी तक विभिन्न टैक्स चुकाना पड़ रहा है। मात्र 35-40 फ़ीसदी आय को ही वह अपने परिवार में खर्च कर पा रहे हैं। जिस कारण गरीबों और मध्यम वर्ग के बीच में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। सरकार को लगता है, गरीबों और मध्यम वर्ग की परिवारों के पास बहुत पैसा है। टैक्स लगाने के बाद वह सड़कों पर नहीं आए हैं। इसका मतलब है, वह टैक्स देने में सक्षम है। मंहगाई बढ़ने के बाद भी जनता सड़कों पर नहीं आती है, इसका मतलब जनता, सरकार की टैक्स प्रणाली से संतुष्ट है। अब आम जनता महंगाई और टैक्स का विरोध करने लगी है। जनता सड़कों पर उतरने मजबूर हो रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को टैक्स में राहत देने की जरूरत है। अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों द्वारा टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब इसका विरोध शुरू हो गया है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा राहत देना अब समय की मांग है।

जल जीवन मिशन योजना में हो रहे कार्य में बरती जा रही लापरवाही

रोड के समीप शोल्डर खोदकर सरकारी संपत्ती को पहुंचाया जा रहा नुकसान

इंजीनियर ने दो बार आवेदन दिया थाने पर लेकिन कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा

माही की गूंज,खवासा।

थांदला तहसील मे पीएचई विभाग के अधिन चल रहै कार्य में इन दिनों गुजरात के ठेकेदारों की बल्ले-बल्ले हो रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल जीवन जल मिशन के तहत हर घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना धरातल पर कारगर साबित नहीं हो पा रही है। कई जगह कार्य शुरू हुए 2 साल हो गए लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो कई जगह कार्य में लापरवाही बरती जा रही है लेकिन जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रेग रही है। कई जगह निर्माण के नाम पर टंकियों में भ्रष्टाचार किया जा रहा हैं तो कई ग्राम पंचायत में नल स्टैंड ना लगाते हुए ऐसे ही नलियों को छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है कि, झाबुआ जिले में पीएचइ विभाग के अधिकारियों को मालूम नहीं है, उनको सब मालूम और जानकारी होने के बाद भी कार्यों को ठंडे बस्ते में डाल रखा हैं। समय अवधि मे कार्य पूरा नहीं किया फिर भी ठेकेदार के ऊपर आज दिन तक कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। पूर्व में भी तलावड़ा,रतनाली एवं सागवा का मामला सुर्खियों में रहा लेकिन फिर भी विभागीय अधिकारी व सब इंजीनियर ने ठेकेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ प्रतीत होता है कि, उनकी मिली भगत से ठेकेदारों की पांचो उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में नजर आ रहा है, कार्य तो घटिया कर ही रहे हैं लेकिन लोगों की जान भी जोखिम डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ठेकेदार सड़क के नजदीक से खुदाई कर रहे हैं जिससे कभी किसी की जान भी जा सकती है। कुछ ऐसा ही मामला थांदला जनपद की ग्राम पंचायत बड़ी धामनी में सामने आया। जहां रतलाम-झाबुआ,फुलमाल मार्ग की सड़क के समीप बड़ी धामनी में खवासा तरफ आने वाले रास्ते के समीप शोल्डर खोद दिए गए। मुख्य सड़क के नजदीक से ही शोल्डर इतने खोदे गए की थोड़ी सी बाईक बारिश के समय पीसले तो जान भी जा सकती हैं। रोड के नजदीकी काले पाइप गाड़े जा रहे हैं, जबकी नियम के मुताबित ठेकेदार को एमपीआरडीसी अधिकारी से परमिशन लेना थी। लेकिन ऐसा नहीं किया और अवैध तरिके से सडक के समिप ही नाली खोद दि। जबकि पूर्व में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव व कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दे चुके है कि, जहां अगर रोड के समीप शोल्डर खोदना हो तो कट्टर से काटे न की जेसीबी से नाली खोदे। ठेकेदार की थोड़ी सी लापरवाही कभी किसी की जान पर बन सकती है यह सख्त हिदायत थी। पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ ठेकेदारों को भी निर्देश दिये थे। लेकिन फिर भी कई जगह ठेकेदार नियमों व आदेशो को दरकिनार कर बिना परमिशन के जेसीबी से शोल्डर(नाली) को खोद कर पाइप बिछाए जा रहे हैं। लेकिन विभागीय कार्रवाई करने के बजाय ठेकेदार को संरक्षण देते हुए नजर आते हैं। पाइप रोड के समीप गाड़ने के वक्त शिकायत किसी ने एमपीआरडीसी के अधिकारियों को की थी। जिसके बाद एमपीआरडीसी के रतलाम-झाबुआ,फुलमाल मार्ग के सब इंजीनियर रामगोपाल हटीला मौके पर पहुंचे। बिना परमिशन के खोदे गए शोल्डर व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर एमपीआरडीसी के सबडिवीजन कार्यालय धार से एक लेटर थांदला थाने में भी पहुंचा। ठेकेदार ने अवैध तरीके से सोल्डर को खो दिया व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करने की लिखित रिपोर्ट दर्ज की लेकिन अब तक ठेकेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बताते हैं कार्य करने वाली गुजरात की वाइब्रेट डेवलपर कंपनी अहमदाबाद द्वारा बड़ी धामनी मे कार्य करवाया जा रहा है।

मामले में थांदला पीएचई सबडिवीजन के सब इंजीनियर कुसुम कवचे से जानकारी ली तो उन्होंने बताया, मैंने तो ठेकेदार को मना कर दिया था कि, मेन रोड के नजदीक से ना खोदे लेकिन उन्होंने रात में इस तरह से खोद दिया। फिर भी मैंने मना कर दिया है और जो शोल्डर खोद दिए हैं उसकी भरपाई ठेकेदार कर देगा कहकर इति श्री कर दी।

वही मामले में वाइब्रेट डेवलपर कंपनी के ओनर डीआर पटेल अहमदाबाद से उनके मोबाइल से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि, परमिशन तो नहीं ली थी लेकिन जहां रोड पर शोल्डर होते हैं वहा पाइप बिछाकर व्यवस्थित शोल्डर को वापस कर दिया गया है। हमने परमिशन नहीं ली थी यह सत्य है लेकिन वहां के सुपरवाइजर अन्य मजदूर ने जेसीबी से खोद दिया था लेकिन जल्द ही उसको सही कर दिया जाएगा।

वही मामले में एमपीआरडीसी के धार डिवीजन के सब इंजीनियर रामगोपाल हटीला ने बताया, अवैध तरीके से सोल्डर को खोद दिया और इधर बारिश का समय है कभी किसी की जान भी जा सकती है। रोड को इस तरह से ठेकेदार नहीं खोद सकता है,हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया। उनके द्वारा एक लेटर थाने पर दिया गया है संबंधित फर्म पर कार्रवाई करने के लिए।

तिरंगा यात्रा को लेकर हुई बैठक

माही की गूंज,सारंगी।

भाजपा युवा मोर्चा सारंगी मंडल की तिरंगा यात्रा निकालने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। मंडल अध्यक्ष सुखराम मोरी ने कार्यक्रम संपन्न करने के लिए उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक मोटरसाइकिल लेकर आने के लिए आहवान करते हुए मार्ग में सुव्यवस्थित तरीके से बाइक रैली को चलाने के लिए मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी हेमंत भट्ट, मंडल अध्यक्ष सुखराम मोरी ,युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष एवं तिरंगा यात्रा प्रभारी जितेंद्र गेहलोत ,सोनू विश्वकर्मा ,मंडल महामंत्री रामचंद्र भूरिया, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुखराम परमार ,जिला मंत्री महेंद्र सिंह चंद्रावत , युवा मोर्चा मंडल महामंत्री लालसिंह डामर , वरिष्ठ नेता हनुमंत सिंह राठौर, नविन चंद्र सिंह राठौर, रमेश भाई गुर्जर, परमानंद पाटीदार, सुरेशचंद्र परिहार, तेजमल सोलंकी, अजय पंवार, संजय उपाध्याय, हैमेन्द्र सिंह राठौर,उप सरपंच रणजीत सिंह राठौर, प्रेम दास बैरागी, प्रकाश डांगी, दशरथ देवदा ,लूणचंद वसुनिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

9 अगस्त की छुट्टी घोषित करने की मांग की

माही की गूंज, थांदला।

विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किए जाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष सोनल जसवंतसिंह भाबर ने कलेक्टर नेहा मीना को पत्र लिखकर विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को सम्पूर्ण जिले में अवकाश घोषित किये जाने की मांग की है। श्रीमती भाबर ने बताया कि, प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किए थे। किंतु वर्तमान सरकार द्वारा अभी तक अवकाश की घोषणा नही की गई है। आदिवासी दिवस जनजातीय समाज की संस्कृति, प्रकृति पूजन और स्वाभिमान का दिन है। जिले में अधिकांश लोग जनजातीय समाज के निवास करते है। इसलिए समाज के दिवस को उत्साहपूर्वक मनाए जाने के लिए 9 अगस्त को स्थानिय अवकाश घोषित किया जावे।

बच्चों ने मनाया फ्रेंडशिप डे

माही की गूंज,थांदला।

बरसात का मौसम सुहाना लगता है ऐसे में प्यार व दोस्ती का आधुनिक पर्व फ्रेंडशिप डे का जबरजस्त उत्साह बच्चों में देखने को मिला। रविवार स्कूल की छुट्टी होने से बच्चों का उत्साह दो गुना हो गया। नन्हें बच्चों ने भी टोली बनाकर हाथों में फ्रेंडशिप बेल्ट लेकर अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़े। एक दूसरे के घर जाकर फ्रेंडशिप बेल्ट पहनाकर हाथ मिलाते हुए मित्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। यह पहला अवसर है जब इन नन्हें बच्चों के माता-पिता को भी अपने बच्चों पर गर्व हुआ कि वे बाल उम्र में भी दोस्ती की अहमियत समझते है व उत्साह से आधुनिक युग के पर्व को मनाते है। सभी बच्चों ने मिलकर खूब मस्ती भी की व पेरेंट्स द्वारा बनाया स्नेक्स व चॉकलेट बिस्किट का भी भरपूर आनंद लिया। उल्लेखनीय है कि 4 अगस्त को विश्व मित्रता दिवस मनाता है। ऐसे में स्कूल, कॉलेजों के दोस्तों के लिये यह आपसी मिलन का पर्व रहा तो अधिकांश अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम व ट्विटर के जरिये मित्रों को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते नजर आये।

जैन श्वेतांबर कल्याण समिति शपथ ग्रहण व अभिनन्दन समारोह सम्पन्न

माही की गूंज, पेटलावद।

तेरापंथ धर्मसंघ के 11 वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी सुशिष्या साध्वी श्री उर्मिलाकुमारीजी आदि ठाणा 4 पावन सानिध्य में तेरापंथ भवन पेटलावद में 'मालवा सभा की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण व मुमुक्षु अभिनन्दन समारोह सम्पन्न हुआ। जिसमे सम्पूर्ण मालवा की 18 सभाओं के साथ चौखले के अन्य क्षेत्र के सदस्यों ने भाग लिया । कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी श्री द्वारा नमस्कार महामन्त्र से हुआ। मालवा सभा के नव मनोनीत युवा अध्यक्ष संजय गांधी को एडव्होकेट राजेन्द्र जी मूणत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। ततपश्चात पूरी कार्यकारिणी को अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलवाई गई। साध्विद्वय ज्ञानयशा जी,रितुयशा जी ने सुमधुर गीतिका का संगान कर परिषद को मंत्रमुग्ध कर दिया। उज्जैन से पधारे पूर्व मालवा सभाध्यक्ष ईश्वरलालजी पटेल, अभातेयुप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पुनीत भंडारी रतलाम व रूपम पटवा पेटलावद सहित पीयूष गोखरू नीमच,मनीष पीपाड़ा उज्जैन , फुलचन्दजी कांसवा पेटलावद, पूनमचंद कोठारी, लालचंद गांधी पंकज मेहता,पंकज जे.पटवा सहित अनेक वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये। साध्वी मर्दुलयशा जी ने युवाशक्ति को प्रेरणा देते हुए बताया कि, आत्मविश्वास के साथ काम करने से हर काम सफल होता है। युवा अध्यक्ष संजय गांधी ने अपने भाषण में बताया कि, समाजजनों ने हमे मात्र 2 वर्षीय कार्यकाल दिया है जिसका पल-पल हमारे लिए कीमती है। यह बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास है इसलिये सदैव तत्पर रहकर समाज की उन्नति और प्रगति का कार्य करना है। टीम से मेरा यही आह्वान है कि, अब बोलने का नही काम को कर दिखाने का समय है। हमको संगठित होकर मजबूती से आगे बढ़ना है, जिससे हर काम का निश्चित लक्ष्य प्राप्त कर पाए। संजय गांधी ने बताया हम संगठन यात्रा पर जाएंगे और मालवा के सभी गांवों नगरों ओर परिवारो से सम्पर्क करेंगे। साथ ही व्यापक स्तर पर विशाल सदस्य संख्या खड़ी कर हमारे आचार्य श्री महाश्रमणजी से मालवा की धरा पर चातुर्मास करवाने की अर्ज करेंगे। श्रद्धानिष्ठ श्रावक तथा 12 की परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक परिणाम लाने वाले समाज के मेघावी बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अपने उद्बोधन में साध्वी श्री उर्मिला कुमारीजी ने कहा कि, समाज का कार्य करने का दायित्व निर्वहन वही व्यकि कर सकता है जिसका मजबूत मनोबल हो, जिसके भीतर बुराई के प्रति घृणा हो,अपने दायित्व का बोध हो, साथ ही जिसमे असीम अनावेश भरा हो , वही व्यक्ति दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर सकता है। कार्यकारिणी को इंगित करते हुए आपने फ़रमाया की पद ओर मद दोनों सगे भाई होते है इसलिये आप अपने पद को समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठा समझ कर श्रद्धाशील,आचारशील एव व्यवहारशील बनकर काम करना श्रेयष्कर होगा। कार्यक्रम का प्रथम सत्र का समापन साध्वीश्री के मंगलपाठ के साथ सम्पन्न हुआ। ततपश्चात पूजा मैरेज गार्डन में उपस्थित परिषद के सहभोज पश्चात द्वितीय सत्र प्रारम्भ हुवा। जिसमे युवा अध्यक्ष ने सबसे आह्वान किया कि आपके मन मे कोई सवाल हो या हमारी टीम अच्छा कार्य कैसे कर पाए ऐसे सुझाव हो तो अपने विचार हमसे साझा करें। परिषद ने बहुत सारे विषयो पर चर्चा कर आगे कार्य करने की रूपरेखा तैयार की। इस अवसर पर पेटलावद के फूलचंद कांसवा को मालवा सभा के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौपी गई।

नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित

माही की गूंज , रायपुरिया।

मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अन्तर्गत जनपद पंचायत पेटलावद की ग्राम पंचायत रायपुरिया के ग्राम छापरापाड़ा में नवीन पेसा ग्राम सभा गठन हेतू प्रस्ताव पारित किया गया। पेसा एक्ट के पेटलावद ब्लाक समन्वयक कैलाश निनामा द्वारा ग्रामवासियों को पेसा कानून के बारे में विस्तार से समझाया। उसके बाद ग्रामवासियों द्वारा सर्व सहमति के आधार पर नवीन ग्राम सभा गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।एवं ग्रामवासियों द्वारा ग्राम छापरापाड़ा का नजरी नक्शा भी बनाया गया। बैठक में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।जिसमें ग्राम पंचायत रायपुरिया के सचिव, मोबेलाइजर, तड़वी सोमजी मुनिया, कोटवार मोहन अरड, सामाजिक कार्यकर्ता राहुल परमार, प्रकाश वाखला एवं अन्य ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

रात भर पुलिस गस्त के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद

माही की गूंज, पारा।

रात में पुलिस गस्त कर बदमाशो पर व अपराधो पर अंकुश लगाने का दावा कर करती है। पर असल में पुलिस सड़क पर गस्त करती रहती है और बदमाश पुलिस को चुनोती देकर अपराधो को अंजाम दे ही देत है ओर पुलिस हाथ धरे ही रह जाती है। इसी तरह रविवार- सोमवार की रात्रि में भी चोकी प्रभारी अशोक बघेल अपने स्टॉफ के साथ गस्त कर रहे थे उसी दौरान बोरी मुख्य मार्ग पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल एक या दो नही बल्कि सात दुकानों पर चोरी करने की कोशिश की। इक्का दुका दुकानों पर 5 से 10 हजार की चोरी को चोट्टो ने चोरी को अंजाम दिया। बाकी दुकानों की शटर को अंट लगाकर तोड़ दी पर किसी कारण वश चोरी करने में नाकाम रहे।

ज्ञात रहे की उक्त स्थान पर पूर्व में भी अज्ञात बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दे चुके है पर उसका पुलिस आज तक खुलासा नही कर पाई।

दुकानों को निशाना बनाया

अजय मेडिकल स्टोर्स संचालक ने बताया कि, मेरी दुकान में अंट लगाया सामान नहीं ले गए। अजय कनेस बताया कि, पूर्व में भी मेरी मेडिकल में चोरी हुई थी दुकान की फाइल व कुछ नगदी ले गए थे जो आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। निखिल पाटीदार कृषि सेवा केंद्र के कीटनाशक व बीज की दुकान है, पाटीदार की दुकान की शटर ऊंची कर दी शटर तोड़ने का प्रयास किया मगर नहीं टूट पाई। सांवरिया ऑटो पार्ट्स की शटर खोल दी थी सामान कुछ नहीं ले गए। राधा स्वामी कोल्ड ड्रिंक की दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे माल कुछ नहीं ले गएं। प्रकाश शेखू रावत कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर ताले तोड़े जहा से हजारों के माल पर चोट्टो ने हाथ साफ किया।

गुजरात कृषि सेवा केंद्र पर प्रकाश वसुनिया के यहां से कुछ सामान ले गए। अरीवा ऑटो पार्ट्स आर्यन खान की दुकान की शटर खोलने का प्रयास किया बदमाश यहा नाकाम रहे।

ग्रामीणों का क्या कहना

पारा ग्राम के नागरिकों का कहना है कि, जीप से पुलिस गस्त करती है जबकी पुलिस को पैदल ही गस्त करना चाहिए तभी चोरी जैसी घटनाएं व रात में होने वाले काले धंधों पर अंकुश लग सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि, रात में पुलिस जीप का सायरन सुनकर अज्ञात बदमाश सतर्क हो जाते हैं औरं घटना को अंजाम दे जाते है।

संपादकीय

ब्रिटेन में उग्र दक्षिणपंथ

ब्रिटेन में दक्षिणपंथी हिंसा की लहर के बीच आप्रवासियों व मुस्लिमों को निशाना बनाया जाना बेहद चिंता का विषय है। सोशल मीडिया के जरिये भ्रामक प्रचार से समूह विशेष पर हमले ब्रिटिश समाज में विकट होती स्थिति को दर्शाता है। दरअसल, गत 29 जुलाई को साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट की थीम डांस पार्टी में तीन बच्चियों की नृशंस हत्या के बाद ब्रिटेन के कई शहरों में दंगे भड़क उठे। इस घटना में दो वयस्कों के साथ कई अन्य बच्चे भी घायल हुए थे। इसके बाद पूरे ब्रिटेन में दक्षिणपंथी आंदोलनकारियों ने इस घटना का इस्तेमाल नफरत को बढ़ावा देने और अराजकता भड़काने में किया। कालांतर में हिंसा महज विरोध प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं रही। दुकानें लूट ली गईं, कारों को आग लगा दी गई, मस्जिदों और एशियाई स्वामित्व वाले व्यवसायों को निशाना बनाया गया। यह चिंताजनक स्थिति ब्रिटिश समाज में पैर पसारती मानसिक रुग्णता को ही दर्शाती है। दरअसल, ब्रिटिश समाज में आप्रवासियों के प्रति धुर दक्षिणपंथियों की कटुता छिटपुट घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में ही नजर नहीं आती, बल्कि ये घटनाक्रम ब्रिटिश समाज में व्यापक सामाजिक चिंताओं और राजनीतिक विफलताओं का भी परिचायक है। दरअसल, कई दक्षिणपंथी राजनेताओं ने आप्रवासन और सांस्कृतिक एकीकरण के बारे में गलत धारणाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने विभाजनकारी एजेंडे के लिये समर्थन जुटाने के लिये खतरनाक ढंग से गलत सूचनाएं फैलायीं। कहा गया कि हमलावर एक आप्रवासी मुस्लिम था। हालांकि प्रधानमंत्री स्टार्मर ने दंगों को सुनियोजित साजिश बताते हुए घटनाओं की निंदा की है, लेकिन अभी ब्रिटिश समाज में सामाजिक समरसता बनाये रखने के लिए बहुत कुछ किया जाना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर एक सप्ताह में हिंसक गतिविधियों में शामिल करीब चार सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। दंगइयों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे पुलिस से संघर्ष करते नजर आ रहे थे। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति और आप्रवासियों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे।

दरअसल, हाल के दिनों में देखने में आया है कि कई देशों में हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये ऑनलाइन सूचनाओं को गलत ढंग से प्रसारित व प्रचारित किया गया। वास्तव में भ्रामक सूचनाओं के तंत्र पर अंकुश लगाने के लिये ठोस प्रयास किये जाने की जरूरत है। देखने में आया है कि सुनियोजित ढंग से प्रचारित सूचनाएं लोगों को कट्टरपंथी बनाने और हिंसा को भड़काने के लिये प्रयोग की जाती हैं। सोशल मीडिया को एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल, ब्रिटिश सरकार को अंतर्निहित उन सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है जिसके जरिये दक्षिणपंथी स्थानीय लोगों का भावनात्मक दोहन करते हैं। मसलन बेरोजगारी और अपर्याप्त सामाजिक सेवाओं की समस्या को दूर करना चाहिए, जिसके बहाने आप्रवासियों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया जाता है। निश्चित रूप से ऐसे भय के माहौल में सहिष्णुता और एकता के मूल्यों को बनाये रखने की सख्त जरूरत है। भविष्य में प्रवासियों के खिलाफ ऐसी हिंसा दोबारा न पनपे ब्रिटिश सरकार को अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा और समावेशन को सुनिश्चित करना चाहिए। अब चाहे वे किसी भी देश से आए हों। मीडिया और राजनीतिक नेताओं से जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद की जानी चाहिए। उन्हें नफरत फैलाने वाली भड़काऊ बयानबाजी से बचना चाहिए। ब्रिटेन में डेढ़ दशक बाद व्यापक रूप से पनपे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। दरअसल, इस दौरान दक्षिणपंथियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस को भी निशाना बनाने से परहेज नहीं किया। इस घटनाक्रम के चलते प्रदर्शनकारी तथा आप्रवासियों के समर्थक कई बार आमने-सामने नजर आए। एक पक्ष कह रहा था कि ब्रिटेन को बाहरी लोगों से मुक्त कराया जाए तो दूसरी तरफ आप्रवासियों का समर्थन करने वाले नारे लगा रहे थे कि यहां शरणार्थियों का स्वागत है। बहरहाल, हाल की हिंसक घटनाओं ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री स्टार्मर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि, उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए हैं। बकायदा इस संकट को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सुरक्षा अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक भी बुलाई गई। निश्चित रूप से दक्षिणपंथियों की हिंसा से सख्ती से निपटने की जरूरत है।

आखिर हसीना कैसे शुमार हुई तानाशाहों में

ज्योति मल्होत्रा

सोमवार सायं को बांग्लादेश में भड़के अराजक आंदोलन के दौरान एक 'प्रदर्शनकारी' द्वारा बंगबंधु मुजीबुर्रहमान की प्रतिमा पर हथोड़ा चलाने की तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली था। हमें लगता है यह किसी आंदोलनकारी छात्र का काम नहीं हो सकता-कतई नहीं -भले ही वह बंगबंधु की बेटी से कितना भी नाराज़ क्यों न हो। यहां तक कि अगर शेख हसीना उस वक्त भी चुप रहीं, जब पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे आंदोलन में 'देखते ही गोली मार दो' आदेश के बाद सुरक्षा बलों के हाथों 300 से अधिक मारे गए और यह हुक्म और किसी ने नहीं बल्कि उनकी आवामी लीग पार्टी के महासचिव ओबेदुल कादर ने दिया था। यदि बंगबंधु जीवित होते तो वे भी इन वैचारिक तौर पर विकृत लोगों का निशाना बन जाते, जिन्हें 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए हुए लासानी युद्ध के बारे में तो बहुत कम या ज़रा इल्म नहीं है।

वे बांग्लादेश के उस राष्ट्रपिता की पुत्री हैं जो कभी गलत नहीं कर सकते थे, शेख हसीना तो लोकतंत्र की बेटी हैं, जो 15 अगस्त 1975 की मनहूस रात को हुए नरसंहार से बच गई थीं दूजब उनके बाकी परिवार को विद्रोहियों द्वारा क्रूरता से खत्म कर दिया गयादृ सिर्फ इसलिए कि क्योंकि वे और उनकी बहन रेहाना, उस दिन धानमोंडी के पुश्तैनी घर में मौजूद नहीं थीं। आज हसीना को उन तानाशाहों की जमात में रखा जा रहा है जो अपनों का खून बहाने से पहले जरा नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें यही करना पड़ता है, अपना बचाव सर्वप्रथम जो होता है।

पर यह सब हो गुजरने की नौबत बनी कैसे? शेख हसीना कैसे ओबेदुल कादर को अनुमति दे सकती हैं कि जो कोई प्रदर्शन करने की जुर्रत करे, उसे मार डाला जाए? स्पष्टतः 1971 की क्रांति खुद को दोहरा रही है। यह अपने संतान खुद खाने जैसा है। बताया जा रहा है, ढाका में दो हफ्ते पहले हुई अभागी पत्रकार वार्ता में कादर ने कहा कि यदि छात्र अपना आंदोलन बंद कर घर वापसी नहीं करते तो 'इन्हें सीधा करने' को अपनी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को हुक्म देना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब है कि शेख हसीना की पार्टी वालों ने ढाका और चटगांव में प्रदर्शनकारी निर्दोष विद्यार्थियों पर गोलियां चलाईं? यह अभी जांच का विषय है। लेकिन यूनिसेफ ने कहा है कि जुलाई माह के आंदोलन में कम से कम 32 छात्र मारे गए हैं।

यह कैसे हो सकता है कि शेख हसीना जिन्हें अपना पूरा परिवार नरसंहार में गंवाया हो और उसके बाद दिल्ली के पंडारा रोड के एक घर में अपनी बहन रेहाना और किशोर भाई रसेल के साथ बतौर राजनीतिक शरणार्थी रहना पड़ा, और इस दौरान उनके प्रिय बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त ताकतें सत्तासीन हो गईंदृ क्योंकर उन्होंने खुद को इतना बिखरने दिया कि उन्हीं तानाशाहों का प्रतिबिम्ब बन गईं, जिनसे कभी नफरत थी?

अब जबकि उन्हें दिल्ली के पास हिंडन वायुसेना अड्डे पर या उसके पास 'भारतीय सेफ हाउस' में रहना पड़ रहा है और केवल एक घंटे की दूरी पर, दिल्ली में रह रही और विश्व स्वास्थ्य संगठन में नौकरी कर रही अपनी बेटी साइमा वाज़ेद से मिलने तक की अनुमति नहीं है, तो शायद वे कुछ समय निकालकर अपने भीतर झांकेगी कि कैसे और क्यों उन्होंने इस मनहूस स्थिति को बनने दिया।

जनवरी माह में, जब विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा दूसरी बार भी आम चुनाव का बहिष्कार किए जाने के बाद, शेख हसीना ने इस निर्णय पर हेकड़ी पूर्ण रुख अख्तियार करते हुए, बीएनपी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, यह एक तरह से उनके चेहरे पर थूकने जैसा था। भले ही ये दो महिलाएं, शेख हसीना और पिछले सालों से अस्वस्थ चल रही बीएनपी प्रमुख खालिदा ज़िया, एक-दूजे को सख्त नापसंद करती हों, किंतु लोकतंत्र के पहले नियम का तकाज़ा है कि चाहे आप किसी विपक्षी नेता से कितनी भी दिली नफरत क्यों न करते हों, फिर भी उसे अपनी बात कहने का मौका तो देना ही पड़ेगा।

लेकिन हसीना अड़ी रहीं दृ और भारत सरकार के पास उनकी दलीलों को मानने के सिवा कोई चारा नहीं रहादृ लेकिन यदि भारत उनके अधिनायकवादी तौर-तरीकों से चुनाव के जरिये सत्ता में वापसी का समर्थन न करता रहता तो बंगाल की खाड़ी उन मगरमच्छों का आशियाना बन जाती, जिनका प्रशिक्षण और पोषण पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान करता आया है। विडंबना है कि वह आकलन भी एकदम सच था। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी सहित अपने से पहले के प्रधानमंत्रियों की भांति नरेंद्र मोदी को भी अहसास रहा कि भारत के पास शेख हसीना का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब 2001 से 2006 के बीच बीएनपी सत्ता में रही, तब न केवल भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके को गहरी उथल-पुथल में धकेला गया बल्कि पाकिस्तान परस्त तत्वों ने चटगांव बंदरगाह से होकर बांग्लादेश में आधुनिक हथियारों की खेपों की खेपें उतारीं।

यह एकदम सच है कि शेख हसीना की ढाका में वापसी भारत के लिए एक बड़ा वरदान रही। केवल 1971 के नाते से नहींदृयह सरगर्मी आरंभ से रही, जब विशेष रिश्ता कायम हुआ, जो न केवल मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना के बीच था बल्कि दोनों मुल्कों के नागरिकों के मध्य भी दृ और ये संबंध शेख हसीना के पिछले 15 सालों के प्रधानमंत्रित्व काल में भी बने रहे।

भारत और शेख हसीना के नेतृत्व वाले बांग्लादेश के मध्य राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में एक बिल्कुल नई किस्म की साझेदारी बनी, जो बाकी दक्षिण एशिया के लिए आदर्श उदाहरण बनी। सड़क, रेलवे, पारगमन का अधिकार, आम नागरिकों को आने-जाने की अनुमति, रक्षा क्षेत्र में मदद, जो कोई भी नाम लें, उस क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश की जुगलबंदी कायम रही।

तब फिर ऐसा क्या हुआ? सोमवार को ढाका में बांग्लादेशी आंदोलनकारी द्वारा शेख मुजीब की मूर्ति के सिर को हथौड़े से तोड़ने और देशभर में हिंदू परिवारों पर हुए हमले साफ दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे से कोई ताकतें यह सब करवा रही हैं। सबसे बड़ा शक पाकिस्तान परस्त जमात-ए-इस्लामी संगठन पर है। वे लौट आए हैं। बांग्लादेश में इतिहास कभी भी वास्तव में इतिहास नहीं रहा। अब पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए बंगाल की खाड़ी में 'खेला' करने के लिए यह परिस्थिति जन्य मौका है।

यह भी उतना ही सच है कि शेख हसीना के सिवाय एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास जमात-ए-इस्लामी और इसके राजनीतिक मुखौटे बीएनपी से मुकाबला करने का माद्दा हो। लेकिन हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब जबकि हिंडन वायुसेना अड्डे पर वे ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय द्वारा राजनीतिक शरण की अनुरोध स्वीकार करने की बाट जोह रही हैं, शायद लंदन से अनुमति आने तक उनके लिए ढाका में बने रहना सुरक्षित न होता। अवश्य ही उन्होंने भारत से अस्थाई पनाह देने की गुहार लगाई होगी। उन्हें आने देकर मोदी सरकार ने सही किया है। और दोस्त होते किसलिए हैंदृ भले ही अगला गलत क्यों न हो।

बाढ़ में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाएं

आलोक पुराणिक

दिल्ली वाले शिकायत कर रहे थे जून में कि हाय-हाय हरियाणा वाले, हिमाचल वाले पानी न छोड़ते, तो दिल्ली प्यासी रह जाती है। अगस्त तक शिकायत उलटी हो गयी कि हाय हरियाणा वाले, हिमाचल वाले इतना पानी छोड़ दे रहे हैं कि दिल्ली डूब रही है।

दिल्ली वालों का एक काम पक्का है, वह है शिकायत करना। दिल्ली में तरह-तरह की सरकारें हैं, सबका एक ही काम है एक-दूसरे की शिकायत करो। पानी बहुत ज्यादा बह रहा था, क्यों बह रहा था। फलां सरकार को पानी को लाइसेंस देना चाहिए बहने का। अगर बिना लाइसेंस के पानी बहे, तो पानी को अरेस्ट कर लेना चाहिए। धूप पर चालान कर लेना चाहिए, पर नेताओं को बकवास के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। दिल्ली डूब जाती है जुलाई-अगस्त में हर साल, पर नेता बारहों महीने डूबे रहते हैं, आरोपबाजी में।

अब कुछ नहीं हो सकता। बाढ़ आयेगी, लोग डूबेंगे, पुल टूटेंगे, सड़कें बहेंगी हर साल कोई कुछ न कर सकता। हां, दिल्ली-हरियाणा के पुल कह सकते हैं कि हम शर्मदार पुल हैं, बारिश आये, तो हम गिर जाते हैं। बिहार के पुल बहुत ही नालायक किस्म के पुल है, बिना बारिश के ही गिर जाते हैं, बेवजह। पुल गिर जाते हैं, पब्लिक मर जाती है। नेता हेलिकाप्टर पर सर्वे करते हैं।

अब वक्त है कि बाढ़ टूरिज्म को प्रमोट किया जाये। कुछ कमा ही लिया जाये बाढ़ से। देश-विदेश से पर्यटकों को लाया जाये, उन्हें पुल जादू दिखाया जाये। देखो वह पुल दिख रहा है न बस पांच मिनट की बारिश में वह गायब हो जायेगा। इंग्लैंड का टूरिस्ट कहेगा कि हमारे यहां तो पुल कई शताब्दियों तक खड़े रहते हैं। उन्हें ज्ञान दिया जायेगा कि दुनिया क्षणभंगुर है। पुल कुछेक हफ्ता भंगुर है। सब भंग हो जाता है। जो आया है, वह जायेगा। पुल आया था, पुल को जाना था। पुल चला गया। जाने वाले को कौन रोक पायेगा।

पर मेरा टेंशन दूसरा है। कभी ऐसा न हो कि हम बतायें फिनलैंड के टूरिस्ट को कि देखो पुल पांच मिनट में बह जायेगा और पुल कतई बेशरम निकल जाये और बहने से इनकार कर दे। वह वहीं का वहीं टिका रह जाये। ऐसे में बहुत बेइज्जती खराब हो जायेगी। ऐसी सूरत में उस पुल को बनाने वाले इंजीनियर को सज़ा देनी चाहिए। दिल्ली में आठ सौ साल पुरानी कुतुबमीनार टिकी हुई है, पर आठ साल पुरानी सड़क गायब हो रही है। मतलब इसमें कुतुबमीनार की ही गलती मानी जानी चाहिए कि टिकी क्यों हुई है। पीडब्ल्यूडी वाले बनाते कुतुबमीनार तो आठ सौ सालों में सोलह सौ बार बना चुके होते। हर दूसरे साल पर टूटती कुतुबमीनार। इस थीम पर अगले साल बारिश में टूरिस्ट बुलाये जा सकते हैं।

परीक्षाओं के लिए जान पर खेलते बच्चे

क्षमा शर्मा

पिछले दिनों से दिल्ली के कोचिंग सेंटर चर्चा में हैं। बारिश के कारण एक बेसमेंट में पानी भर गया और तीन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। उससे पहले यूपीएससी की ही तैयारी करने वाला एक बच्चा बारिश में करंट लगने से मर गया। हर साल लाखों बच्चे अपनी आंखों में तमाम सपनों को लिए यहां आते हैं और जीवन के बहुमूल्य वर्ष लगा देते हैं।

कोचिंग सेंटर्स में देश भर से आए बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। वे किन विकट परिस्थितियों में रहते हैं, इसे मीडिया ने बार-बार दिखाया और बताया है। कितनी कम जगह के लिए उन्हें भारी किराया देना पड़ता है। कैसा खाना मिलता है। मकान मालिक बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा लेते हैं। उस पर रात-दिन की मेहनत। लेकिन जब तक कोई हादसा नहीं होता, कोई नहीं जागता। न सरकार, न कोचिंग सेंटर्स के मालिक, न ही बच्चे, न बच्चों के माता-पिता। मीडिया भी। क्योंकि ये कोचिंग सेंटर्स बड़े विज्ञापनदाता भी हैं। आखिर इनसे कौन दुश्मनी मोल लेकर अपनी आय का नुकसान करे। न ही सरकारी अधिकारियों को कभी इस बात का खयाल आता है कि वे उन चीजों को अनदेखा कर रहे हैं जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। हां, जब दुर्घटना हो जाती है, तब जिम्मेदारी एक से दूसरे पर डाल दी जाती है।

फिल्म बारहवीं फेल में भी हम ये सब देख चुके हैं। यह फिल्म बहुत सफल भी हुई थी। बच्चे ही नहीं उनके माता-पिता चाहते हैं कि किसी तरह बच्चा आईएएस या, आईपीएस, अथवा अन्य सेवाओं में एक बार आ भर जाए तो न केवल उसकी जिंदगी बन जाए बल्कि माता-पिता की भी और दहेज भी मोटा मिले। एक बार एक खबर पढ़ी थी कि जो बच्चे आईएएस बन जाते हैं, उनका नाम लिस्ट में देखकर उनके घर में बड़ा वाहन रुपये लेकर लोग पहुंच जाते हैं। और रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। यूपीएससी का इम्तिहान देने के लिए हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं जबकि चयन कुछ ही का होता है। एक सफल के पीछे हजारों असफल खड़े रहते हैं। कई-कई बार तो दशकों इसमें निकल जाते हैं, मगर सफलता के साथी सब हैं असफलता की कहानी कोई नहीं कहता। न ही उस संघर्ष और जी तोड़ मेहनत के बारे में बताया जाता है कि वर्षों तक अठारह-बीस घंटे मेहनत करने और सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद कुछ हाथ नहीं आया।

आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों की सफलता का प्रतिशत औरों से ज्यादा है, इसीलिए बच्चे दिल्ली आते हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या में बच्चे बिहार से आते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2002 से 2012 में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अठारह हजार, एक सौ चौहत्तर बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। मगर सफल सिर्फ दो हजार, दो सौ इकतालीस बच्चे ही हुए थे। सफलता का प्रतिशत इतना कम होने पर भी इस परीक्षा की तैयारी करने वाला हर बच्चा सोचता है कि वह अपने परिश्रम से जीत हासिल कर लेगा, पर ऐसा होता बहुत कम के साथ है।

यूपीएससी को कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। अफसोस होता है कि बच्चों के परिजन, साथ में जहां रहकर ये तैयारी करते हैं वे सेंटर्स, न इनके स्वास्थ्य का खयाल रखते हैं न इनकी मामूली सुविधाओं का। ये पैसे बरसाने वाली मशीनें हैं, जो जितनी बड़ी संख्या में आएंगी लोगों की जेबें उतनी ही फूलती जाएंगी। तभी तो दिल्ली में कुल कोचिंग सेंटर्स की संख्या पांच सौ तिरासी है और सिर्फ सड़सठ के पास सुरक्षा मानकों को पूरे करने वाले प्रमाण पत्र हैं। आखिर बिना सुरक्षा मानक पूरे किए इन सेंटर्स को क्यों चलने दिया गया।

फिर कोचिंग सेंटर्स हमेशा अपनी सफलताओं को बहुत रंगीन बनाकर पेश करते हैं। बहुत से इसमें झूठ-सच का सहारा भी लेते हैं। इसमें एक उदाहरण देना काफी होगा। करीब सत्ताईस-अट्ठाईस साल पहले एक युवा का न केवल आईआईटी बल्कि देश के बहुत से इंजीनियरिंग संस्थानों में चुनाव हुआ था। जैसे ही रिजल्ट आया कोचिंग संस्थानों से फोन आने लगे कि वह युवा अपना फोटो उन्हें छापने की अनुमति दे। जिसमें वे कह सकें कि इस युवा ने इतनी सफलता इसलिए पाई कि अमुक संस्थान से ट्रेनिंग ली थी। वे इसके लिए बड़ी रकम देने को भी तैयार थे। जबकि इस युवा ने खुद ही पढ़ाई की थी। इस युवा ने कोचिंग संस्थान वालों से मना कर दिया। ऐसा आज भी होता है। कोचिंग संस्थान चाहे यूपीएससी के हों, इंजीनियरिंग के हों, अथवा मेडिकल या एमबीए के, अधिकांश की कहानी कमोबेश एक जैसी ही होती है। कोटा में भी यही हाल देखने को मिलता है। वहां तो और भी कम उम्र के बच्चे मेडिकल की तैयारी करने आते हैं। बहुत बार इतने निराश होते हैं कि जान दे देते हैं।

लेकिन अन्य परीक्षाओं के साथ यूपीएससी की कहानियां बेहद दर्दनाक हैं। खास तौर से तब जब वे असफलता से जुड़ी हों। बहुत बार इस आशा में कि बच्चा बड़ा अफसर बन जाएगा, माता-पिता अपनी जमीन, खेत मकान सब कुछ बेच देते हैं, कर्ज ले लेते हैं, मगर जरूरी नहीं कि उनका बच्चा सफल ही हो। और कई बार ऐसा होता है कि एक सफलता की आशा में पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। भारत में माता-पिता का ध्यान अक्सर सरकारी नौकरी पर रहता है। और यदि नौकरी सरकारी है और ऊपरी कमाई वाली भी है तो कहना ही क्या। क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो जीवन भर के लिए पक्की समझिए। इसीलिए विवाह के मामले में भी लोग उन लड़कों को पसंद करते हैं जिनकी सरकारी नौकरी होती है।

कई साल पहले यह लेखिका एक ऐसे दक्षिण भारतीय लड़के से मिली थी जो बहुत पढ़ा-लिखा था। अपने हुनर में माहिर था, मगर बड़ी उम्र हो जाने के बावजूद उसकी शादी दो कारणों से नहीं हो रही थी, एक तो उसकी सरकारी नौकरी नहीं थी और दूसरे वह विदेश में नौकरी नहीं करता था। दोनों में से एक भी बात होती तो शायद उसकी शादी समय पर हो गई होती। उत्तर भारत में भी ऐसी ढेरों कहानियां मौजूद हैं। जो लोग तमाम प्रयासों के बावजूद यूपीएससी में सफल नहीं हो पाते, इसका दुःख उन्हें जिंदगी भर सालता रहता है। अपने ही किसी साथी को बड़ा अफसर देख उनका दुःख और बढ़ जाता है। फिर जिस सपने को लेकर दिल्ली आए थे, वह पूरा नहीं हुआ तो वे अपने नाते-रिश्तेदारों, अड़ोसी-पड़ोसियों की नजर में गिर जाते हैं। तरह-तरह का अपमान झेलते हैं।

समाज में शक्ति और अधिकार के प्रति इतना सम्मान है कि बाकी मानवीय गुण पीछे छूट जाते हैं। इस मामले में महान लेखक जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंद गुप्त का ही पहला वाक्य याद आता है-अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है।

अवैध मदरसे में सब कुछ ठीक बताने का बोला झूठ

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने एडीएम को लगाई फटकार

माही की गूंज, रतलाम।

बगैर मान्यता लिए चल रहे अवैध मदरसे में धार्मिक व स्कूली शिक्षा के नाम पर प्रदेश के कई जिलों से लाई गई बच्चियों को बेहद खराब हालात में रखे जाने के मामले में अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण अधिकार आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा के दौरे में मदरसे के अवैध रूप से संचालन करने की बात सामने आई थी।

डॉ शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के बाद प्रशासन की ओर से एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव मदरसे में जांच के लिए पहुंची थी। एडीएम ने निरीक्षण के बाद मीडिया को दी गई जानकारी में मदरसे के हालात लगभग ठीक होने की बात कही थी और यह स्वीकार किया था कि मदरसे से कुछ कैमरे हटा लिए गए हैं, लेकिन वहां से डीवीआर जब्त नहीं की गई। प्रशासन के स्तराविया पर अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एडीएम पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एडीएम को प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की अनुशंसा भी की है।

कैमरे पाए गए

मध्यप्रदेश बाल आयोग की सदस्य ने निरीक्षण के दौरान रतलाम में एक अवैध मदरसे में लड़कियों के कमरों में कैमरे लगे पाये हैं। दूसरे शहरों/राज्यों से ला कर लड़कियों को वहां रख कर उनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा है यह संविधान का उल्लंघन है। इस मामले में बाल आयोग सदस्य ने कैमरे की रिकॉर्डिंग की डीवीआर जब्त करने के मौखिक निर्देश तत्काल दे दिये थे, डीवीआर जब्त की जानकारी प्रशासन से आना बाकी है जिसकी प्रत्याशा में आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जाना बाकी है।

इसके पूर्व ही ये मैडम जो कि वहां की बतायी जा रही हैं ने मदरसे पहुँच कर मदरसे की प्रवक्ता की तरह बयान दे कर मदरसे को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में प्रशासन को नोटिस जारी कर रहे हैं साथ ही बाल अधिकार क़ानूनों पर इन एडीएम को प्रशिक्षण दिये के लिए भी सरकार को अनुशंसा कर रहे हैं।

गड़बड़ी तब उजागर हुई जब मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य डॉ. निवेदिता शर्मा ने खाचरौद रोड स्थित दारुल उलूम आयशा सिद्धीका लिलबिनात का निरीक्षण किया।

यहां खुले फर्श पर करीब 30 से 35 बच्चियां सोती पाई गई। कमरे में बच्चों की सुविधा के लिए कोई इंतजाम नहीं मिले थे। करीब आठ वर्षीय एक बच्ची तो तेज बुखार से ग्रस्त मिली। इस पर डॉ. निवेदिता ने जमकर नाराजगी जाहिर की व कार्रवाई के निर्देश दिए।

पहले भी अवैध मदरसों के मामले सामने आए थे

रतलाम जिले में अवैध मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को रखे जाने के मामले पहले भी सामने आए हैं। निरीक्षण के दौरान पता चला कि यह मदरसा महाराष्ट्र के 'जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुआ' से संबंधित है।

दल ने वहां पाया कि मदरसे में करीब 100 बच्चियों को रखा गया है, जिनमें से आधे से अधिक का नाम किसी अन्य शासकीय स्कूल में दर्ज है। मदरसे परिसर में ही 10वीं कक्षा तक का स्कूल भी संचालित है, जिसकी सोसायटी का पंजीयन वर्ष 2012 में हुआ था, लेकिन मान्यता 2019 में ली गई।

मदरसे के अंदर साफ सफाई की कमी दिखी, इसके साथ ही दो बच्चियां ऐसी भी मिली जिनके माता-पिता नहीं है। ये बच्चे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में भी पंजीकृत नहीं पाए गए। इसके अतिरिक्त हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए मिले, इसमें बच्चियों की निजता का भी ध्यान नहीं रखा गया था।

घर पहुंची महिला ने दरवाजा खोला तो फांसी पर लटकता मिला पति

माही की गूंज, मंदसौर।

जिल के मल्हारगढ़ नगर की काशी कॉलोनी में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने यह कदम क्यों उठाया अभी कारण पता नहीं चला है। एसआई साजिद मंसूरी ने बताया कि, मंगलवार दोपहर 12 बजे काशी कॉलोनी में 40 वर्षीय कचरूलाल पुत्र जगदीश बलाई निवासी मल्हारगढ़ ने अपने मकान में छत पर रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। पत्नी नीतू आंगनबाड़ी में सहायिका है।

फंदे से उतारकर ले गए थे अस्पताल

वह घर पहुंची व दरवाजा खोला तो पति को फंदे पर लटका देख बेसुध हो गई। जिसके बाद आसपास के लोगो ने युवक को फंदे से उतारा व पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद उसे मल्हारगढ़ अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पीएम कर शव स्वजनों के सुपुर्द किया। मल्हारगढ़ थाना प्रभारी राजेन्द्र पंवार ने बताया की कचरूलाल उर्फ पप्पू ढाबे पर काम करता था। उसके आत्महत्या के कारण अभी अज्ञात है। पुलिस स्वजन से पूछताछ कर मामले में जांच कर रही है।

ढाबे पर काम करता था युवक

कचरुलाल उर्फ पप्पू मालवीय सांवलिया भोजनालय पर काम करता था। उसकी पत्नी वार्ड छह की आंगनबाड़ी में सहायिका है। एक बेटा व एक बेटी है। मृतक बच्चों स्कूल छोड़कर आया था, उसके बाद उसने यह कदम उठा लिया। रहवासियों के अनुसार कचरूलाल मेहनती था व मिलनसार युवक था। आत्महत्या के कारण का पता नहीं चला है। पुलिस अब इस मामले में उसकी पत्नी और आस-पास के लोगों से बात कर जांच करने की तैयारी में है।

महाकाल लोक की तर्ज पर निखरेगा शिपावरा

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के आलोट विकासखंड में शिप्रा-चंबल नदी का संगम स्थल शिपावरा का स्वरूप अब निखरने वाला है। यह जगह करीब 4000 साल पुरानी ताम्राश्म युगीन सभ्यता के अवशेष समेटे हुए है। शिपावरा के पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हुए यहां महाकाल लोक की तर्ज पर नवनिर्माण होगा।

कलेक्टर राजेश बाथम ने करीब 23 करोड़ रुपये की योजना तैयार करवाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजी है। सिंहस्थ मद से इसमें स्वीकृति मिलना तय माना जा रहा है। पर्यटन और धार्मिक नजरिये से शिपावरा विकास की योजना में पूरे क्षेत्र को शिवआकृति में तैयार किया जाएगा।

शिव के त्रिनेत्र, अर्द्धचंद्रमा आदि आकार में होगा निर्माण

इसके लिए शिव के त्रिनेत्र, अर्द्धचंद्रमा, सर्प आदि शामिल रहेंगे। धर्मशाला, ऑडिटोरियम, वॉच टॉवर की तर्ज पर दीपस्तंभ, बड़े घाट, सड़क, पार्किंग, भव्य प्रवेश द्वार सहित अन्य निर्माण किए जाएंगे। इस काम के लिए हाउसिंग बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

शिपावरा से उज्जैन की दूरी 100 किमी है। तैयारी इस तरह से की जा रही है कि यहां भविष्य में बड़े सांस्कृतिक आयोजन भी किए जा सकें। सिंहस्थ 2028 से पहले निर्माण कार्य पूरा करने की योजना है। इससे इस इलाके में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उल्टे दीयों पर टीका है मंदिर, खुदाई में मिले हैं दीये

शिप्रा नदी शिपावरा में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। इस संगम पर करीब 100 फीट ऊंचे एक टीले पर शिपावरा में दीपेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। इसके उल्टे दीयों पर टीके होने की बात कही जाती है। खुदाई में भी यहां दीये मिलते हैं। आलोट से विक्रमगढ़, खजूरी देवड़ा, रजला, मोरिया होकर शिपावरा तक जाने के बाद आगे करीब ढाई किलोमीटर का कच्चा और पथरीला रास्ता संगम स्थल तक पहुंचाता है।

प्रागैतिहासिक काल के प्रमाण भी यहां मिलते हैं

शिपावरा में प्रागैतिहासिक काल से लेकर परमार और मराठा काल तक की पुरा-संपदा के महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। लोकमान्यता है कि भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव इस स्थल पर छुपे थे। यंत्र-तंत्र लगे परमार स्थापत्य एवं मूर्तिकला के कारण इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। यहां रियासतकालीन शिकारगाह भी बना हुआ है, जिसका प्रयोग जावरा के नवाब किया करते थे।

बहु से झगड़ा हुआ तो रेलवे ट्रैक पर लेट गई बुजुर्ग महिला

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले का एक वीडियो मंगलवार की रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में ट्रैक पर लेटी महिला के ऊपर से मालगाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजर गई। पूरी ट्रेन गुजरने के बावजूद बुजुर्ग महिला को खरोंच तक नहीं आई है। यह घटना कुछ दिनों पहले की बताई जा रही है। बेरछा थाना प्रभारी अंकित मुकाती ने इस घटना की पुष्टि की है।

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला पटरी के बीच में लेटी है। तभी ट्रेन आती है उसके ऊपर से कुछ डिब्बे गुजर जाते हैं। कई डिब्बे गुजरने के बार ट्रेन रूकती है और ट्रेन का स्टाफ नीचे आकर महिला को पटरी से हटाते हैं। उधर पास के ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। महिला पटरी से हटने को तैयार नहीं होती है, उसे जबरदस्ती पटरी से हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया।

बेरछा थाना प्रभारी अंकित ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वायरल वीडियो एक सप्ताह पुराना है?। सुंदरसी निवासी कंचन बाई उम्र 80 साल घरेलू विवाद के चलते ग्राम रंथभंवर के पास रेल की पटरी के बीच आत्महत्या करने के लिए लेट गई थी। मालगाड़ी के कुछ डिब्बे उसके ऊपर से गुजर भी गए। किंतु वह पूरी तरह सुरक्षित है।

बुजुर्ग महिलाको पटरी से हटाकर पूछताछ की गई थी। जिस पर उसने अपने घर वालों के बारे में जानकारी दी। उसके बेटे ईश्वर सिंह को घटनास्थल पर बुलाकर महिला को उसे सुपूर्द किया गया। बेटे ने बताया कि सास बहू में कुछ बातचीत हो गई थी, जिससे वह नाराज थी।

अधिकारियों से मिलवाने के नाम पर मां-बेटी को मंदसौर लाए... नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म

माही की गूंज, मंदसौर।

गृह कलह से परेशान भानपुरा तहसील के गांव की एक महिला व उसकी नाबालिग बेटियों को मंदसौर में अधिकारियों से मिलाने के नाम पर एक युवक ले आया। यहां एक धर्मशाला में रात को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया। मां-बेटी ने भानपुरा थाने पर जाकर प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए नईआबादी थाने मंदसौर भेज दिया है।

गांव से भानपुरा आई थी महिला

पुलिस थाना अधिकारी रोहित कच्छावा ने बताया कि पति-पत्नी के रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर महिला गांव से दो बालिकाओं व दो बेटों के साथ भानपुरा आई। शनि मंदिर में पति से तंग होने का किस्सा पं. मदनमोहन जोशी को सुना रही थी।

भानपुरा निवासी प्रफुल्ल प्रजापति ने पीड़ित महिला से सारी जानकारी लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के सामने मंदसौर में शिकायत करने का सुझाव देते हुए कहा कि हमें भी कल मंदसौर जाना है। मैं अधिकारियों से मिला दूंगा। इस बात पर महिला अपनी दोनों नाबालिग बालिकाओं व दो लड़कों के साथ 30 जुलाई को शनि मंदिर में ही रात रुक गई। एक अगस्त को सुबह पं. मदनमोहन जोशी और प्रफुल्ल प्रजापति के साथ जोशी के साथ ये लोग चार पहिया वाहन से मंदसौर पहुंचे। शाम को प्रफुल्ल प्रजापति ने महिला व चारों बच्चों को श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के पास किसी धर्मशाला में कमरा दिलाया, फिर उनके लिए भोजन लेकर आया।

जानकारी के अनुसार आरोपित परिवार को विश्वास में लेकर उसी कमरे में ही रात रुक गया। 2 अगस्त को तड़के तीन से 3:30 बजे के लगभग बाकी सदस्यों के गहरी नींद में सोते समय पलंग से नीचे सो रही नाबालिग का मुंह दबाकर पीड़िता व परिवार को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया।

पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण

तीन अगस्त को पीड़िता ने अपनी मां के साथ भानपुरा आकर आरोपित के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। नाबालिग की रिपोर्ट पर आरोपित 44 वर्षीय प्रफुल्ल पुत्र मोतीलाल प्रजापति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 64/1 व 64/2 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 में पुलिस थाना भानपुरा पर कायमी कर अग्रिम कार्रवाई हेतु नई आबादी पुलिस थाना मंदसौर को भेजा है।

25 पुलिसकर्मी, 500 सीसीटीवी, 24 घंटे में सिक्योरिटी गार्ड के तीन हत्यारे अरेस्ट

माही की गूंज, मंदसौर।

गरोठ थाने के ग्राम नारिया में पवन चक्की के सुरक्षा गार्ड विशाल प्रजापति की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया हैं। तीनों आदतन चोर हैं और हत्या वाली रात भी मानपुरा के एक वेयर हाउस से सोयाबीन चुराकर आ रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड के पहुंचने पर उसकी हत्या कर दी।

इसलिए कर दी सिक्योरिटी गार्ड की हत्या

तीनों आरोपी वेयर हाउस से सोयाबीन चुरा ने के बाद पवन चक्की के पास सोयाबीन कट्टे में से पिकअप में खाली कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा गार्ड विशाल प्रजापति वहां पहुंचा और पिकअप चेक करने लगा।

सुरक्षा गार्ड मोबाइल पर किसी को पिकअप में सोयाबीन भरे होने की सूचना दे रहा था। इससे आक्रोशित होकर तीनों आरोपितों ने टामी व चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपितों ने हत्या के बाद सोयाबीन को दलौदा मंडी में ले जाकर 75 हजार रुपये में बेच भी दिया।

31 जुलाई को हत्या

एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि 31 जुलाई को 30 वर्षीय श्यामलाल पुत्र कैलाशचंद्र व्यास निवासी कुरावन ने रिपोर्ट की थी कि ग्राम नारिया बुजुर्ग में क्रेशर के पास कच्चे रोड पर पवन चक्की के सुरक्षा गार्ड 30 वर्षीय विशाल प्रजापत की पिकअप में आरोपितों ने धारदार हथियार से सिर, मुंह, चेहरे पर गंभीर वार कर हत्या कर दी है।

फरियादी की रिपोर्ट पर गरोठ थाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 3(5) में प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एसपी अनुराग सुजानिया, गरोठ एएसपी हेमलता कुरील ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए थे।

500 सीसीटीवी खंगाले

पुलिस दलों ने ग्राम खजूरी रुंडा, साठखेड़ा, मेलखेड़ा, बनी, कुरावन, बसई, सीतामऊ, बिलांत्री व दलौदा के रास्तेर तक करीब 500 सीसीटीवी कैमरो के फुटेज की जांच की। गरोठ, शामगढ़, सुवासरा व भानपुरा थाने में पूर्व के गंभीर अपराधों में गिरफ्तार आरोपितों की जानकारी भी मुखबिरों से ली गई।

चाकू मारकर की हत्या

सूचना के आधार पर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे अंसार नदी पुल के पास 32 वर्षीय द्वारकालाल, 24 वर्षीय राधेश्याम बागरी, 42 वर्षीय मोहनलाल बागरी को पिकअप के साथ हिरासत में लेकर थाने पर पूछताछ की गई। इन तीनों ने विशाल प्रजापत की हत्या लोहे की टामी व चाकू मारकर करना स्वीकार किया गया।

न्यूज ब्रीफ

चेतावनी सूचना पटल लगवाने के निर्देश जारी

माही की गूंज, धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के आदेश पर वर्षा ऋतु को देखते हुए तालाबों, नहरों, कुओं, बावड़ियों, झरनों एवं पिकनिक स्थल पर दुर्घटना होने की आशंका को देखते हुए इन स्थानों पर चेतावनी सूचना पटल लगवाने और जिले में पुराने एवं क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हांकित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशानुसार वर्षा ऋतु का समय होने से तालाबोंए नहरोंए कुआए बावड़ियोंए झरनों एवं पिकनिक स्थलों पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इन स्थानों पर चेतावनी सूचना पटल लगाकर उनका रख रखाव करें। साथ ही वर्षा ऋतु होने से पूराने भवन एवं क्षतिग्रस्त भवन के गिरने की संभावना रहती है। जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसके लिए जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रों में पुराने एवं क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हांकित कर संबंधित अधिकारी उनकी सूची तैयार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को डेढ़ वर्ष का कारावास

माही की गूंज, बड़वानी। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमति सीता कनोजे के द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी प्रदीप उर्फ पप्पु पिता कृष्णा आर्यए आयु.24 वर्षए निवासी कलाली मोहल्ला राजपुर थाना राजपुरए जिला बडवानी को धारा 34;2द्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम मे डेढ वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति मीना कुशवाह जिला बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 29 जनवरी 2019 को थाना राजपुर पर पदस्थ प्रधान आरक्षक को आरक्षक के साथ कस्बा भ्रमण के दौरान श्रीराम चौक राजपुर पर मुखबिर से सूचना मिली कि प्रदीप अपने ढाबे के पीछे नौकर दिनेश के साथ मिलकर अवैध रूप से शराब विक्रय कर रहा हैं। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान ढाबे की आड़ में छुपकर देखने पर प्रदीप व दिनेश शराब बेच रहे थे। जिसे पंच व हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर दबिश दी। आरोपी प्रदीप मौके से भाग गया। आरोपी दिनेश से शराब बेचने के लाईसेंस के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया और उसके कब्जे से देशी विदेशी कुल 55ण्58 बल्क लीटर शराब जप्त की व आरोपी को गिरफ्तार कर धारा.34;2द्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दिनेश की मृत्यु हो चुकी है। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आज शहर में बंद रहेगा विद्युत प्रदाय

माही की गूंज, बड़वानी। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री से प्राप्त जानकारी अनुसार 08 अगस्त को प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक 11 केवी एमजी रोड़ फीडर पर मेंटेनेंस का कार्य किये जाने से शहर के एमण्जीण् रोड़ए रोटरी क्लब स्कूलए कोर्ट चौराहाए झंडा चौकए रणजीत चौकए कचहरी रोड़ए नमीनाथ नगरए महावीर नगरए रानीपुराए भवती रोडए पाटी नाकाए माली मोहल्लाए बावनगजाए कोयडीया खोदराए रामकुल्हेश्वरए हरिजन मोहल्लाए सिर्वी मोहल्लाए पाटी रोड़ए साकेत रेसीडेन्सीए देवीसिंग गार्डन रोड़ए बोहरा कॉम्पलेक्सए राजघाट रोड़ए रणजीत क्लबए जेल रोडए सुखविलासए हॉस्पिटल कपाउंडए तिरछी पुलियाए महालक्ष्मी गेस्ट हाउसए झामरिया गार्डनए मदरसा रोड़ए कारंजा चौराहाए फिल्टर प्लांटए सांई हास्पीटलए चूनाण् भट्ठी व आसपास के क्षेत्र में विद्युत सप्लाय बंद रहेगा।

इंदौर में कोविड-19 के 3 मामले, मौसमी बीमारियों का भी बढ़ रहा है प्रकोप

इंदौर।

मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड-19 के मामले फिर सामने आए हैं। अभी तक 3 मरीजों में इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बुधवार को बताया कि शहर में मौसमी बीमारियों के साथ ही कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शहर में अब तक कुल 18 मरीजों में डेंगू, तीन में कोविड ????-19 और एक-एक में स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया की पुष्टि हुई है।

इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉक्टर भूरे सिंह सेतिया ने एएनआई को बताया कि पिछले दो दिनों में तीन महिला रोगियों को कोविड ????-19 पॉजिटिव पाया गया है। इन महिलाओं ने शहर के निजी अस्पतालों में अपना परीक्षण कराया। इनमें से दो महिलाओं को उनकी अन्य बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो बाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाई गईं। उनका इलाज चल रहा है, जबकि एक महिला घर पर ही आइसोलेशन में है।

सेतिया ने कहा कि इसके अलावा 18 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि पिछले दो दिनों में शहर में स्वाइन फ्लू और चिकनगुनिया से पीड़ित एक-एक मरीज पाया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम है। जगह-जगह जलभराव है, जिसमें लार्वा पनपते हैं। हमने ड्रोन भी लाए हैं, जिनके जरिए इमारतों की छत पर जमा पानी में लार्वा का पता लगाया जा रहा है। लार्वा को खत्म करने के लिए दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

इससे पहले जबलपुर जिले के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 11 जुलाई से 6 अगस्त के बीच जबलपुर में स्वाइन फ्लू के कुल 11 मामले सामने आए थे। इनमें से नौ मरीज ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य सेवा जबलपुर के संयुक्त निदेशक संजय मिश्रा ने कहा कि बारिश के शुरुआती दौर में हर साल सर्दी, खांसी और बुखार का प्रकोप बढ़ जाता है। स्वाइन फ्लू एक1एन1 वायरस के कारण होता है और कोविड-19 की तरह यह भी गले का संक्रमण है। 11 जुलाई से अब तक जबलपुर में कुल 11 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिनका जिले के निजी और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज चल रहा था। नौ मरीजों को छुट्टी दे दी गई है।

कहा कि इस बीमारी से घबराने की नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। यह हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें अस्पताल में अलग रहना चाहिए और घर पर रहने से बचना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जो लोग सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित हैं, उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। साथ ही कहा कि डॉक्टर से सलाह और समय पर दवा लेना चाहिए।

हर घर तिरंगा अभियान और 15 अगस्त को जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा

माही की गूंज, धार।

हर घर तिरंगा अभियान और 15 अगस्त को जन उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।किसी भी वार्ड या ग्राम में तिरंगे झंडो की कमी ना होएइसके लिए एनआरएलएम के समूहों को जवाबदेही सौंपी जा रही है। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर ये निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ाएएसपी मनोज कुमार सिंह सीईओ सविता झनियाएएडीएम अश्विनी कुमार रावतएएएसपी इंद्रजीत बाकलवार भी मौजूद थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि झंडों की शत प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से व्यवस्था की जाए। नगरीय निकाय इसके विक्रय केंद्र बनाएँ।प्रयास होना चाहिए कि तिरंगा लोग खरीद कर शान से फहरायें। पूर्व वर्षों के ध्वज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। झंडा संहिता का पालन हो। ग्रामोंएशहरों में तिरंगा रैली निकली जाए। सेल्फ़ी पॉइंट बनें।एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत सतत वृक्षारोपण का अभियान जारी रहेगा।

महाराष्ट्र से आए प्रतिनिधि मंडल ने किया भ्रमण

माही की गूंज, खंडवा।

जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं और विभागीय संरचना की जानकारी लेने के लिए अमरावती महाराष्ट्र से श्री सुरेश वानखेड़े एडिशनल डायरेक्टर एवं सहयोगी दल खंडवा जिले में आया। खंडवा परियोजना प्रशासक श्री विवेक पांडेय एवं सहायक आयुक्त श्रीमती आशा चौहान द्वारा दल का स्वागत किया गया। परियोजना प्रशासक विवेक पांडेय ने विभागीय संरचना की जानकारी दी। सहायक संचालक नीरज पाराशर द्वारा दल को सीएम राइज खार तथा विभागीय आश्रम एछात्रावास तथा निर्माण कार्य का अवलोकन कराया गया। वानखेड़े तथा दल द्वारा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से मिलकर जनजातीय क्षेत्र के उत्थान के लिए व्यापक चर्चा की गई।

प्रथम पुरोहित की पुण्य तिथि मनाई

माही की गूंज, थांदला।

कैथोलिक चर्च थांदला में झाबुआ डाइसिस के प्रथम पुरोहित ईश सेवक फादर चार्ल्स प्लैमेयर की पुण्य तिथि मनाई गई। थांदला चर्च में नौ दिन की नौवेनां प्रार्थना के बाद दिनांक 6 अगस्त को मिस्सा पूजा के समारोह के साथ कैथोलिक डाइसिस झाबुआ के बिशप पीटर खराड़ी के मुख्य आतिथ्य में पुण्य तिथि समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर बिशप खराड़ी ने ईश सेवक फादर चार्ल्स के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा किए 125 वर्ष पूर्व बहुत ही विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने प्रभु ईसा के रूपांतरण पर्व पर भी समाजजनों को विस्तृत जानकारी दी। मिस्सा पूजा में डाइसिस झाबुआ बिशप के साथ डाइसिस झाबुआ सचिव फादर सिल्वेस्टर पल्ली पुरोहितए फादर पीटर कटाराए फादर एडविनए फादर असीमए फादर लूकसए के साथ अन्य फादर भी उपस्थित थे।

30 मरीजों का होगा निःशुल्क लैंस प्रत्यारोपण लायंस क्लब के नेत्र शिविर में 114 मरीजों की आँखें जांची

माही की गूंज, बड़वानी।

सुरेखा जमरे और डॉ अनिता सिंगारे ने के मार्गदर्शन में लायंस क्लब बड़वानी सिटी एवं ज़िला चिकित्सालय बड़वानी के संयुक्त तत्वावधान में 7 अगस्त को चोइथराम नेत्रालय द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़वानी ओर आसपास के जिलों से लगभग 114 नेत्र मरीज अपना ईलाज कराने आए। नेत्र विशेषज्ञ डॉण् आशीष सेन और नेत्र सहायक रविंद्र टेकामए नेत्र सहायक श्री डी के सोनी की टीम ने मरीजों का नेत्र परिक्षण किया । सिस्टर ज्योति बघेल और श्री संजय भावसार ने मरीजों का ब्लड प्रेशर तथा शुगर की जाँच की। लायन हरीश शर्मा ने बताया कि लायंस क्लब बड़वानी सिटी जिला अस्पताल बड़वानी में प्रति माह 2 निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन करता है। जिसमें मोतियाबिंद के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन कर लैंस प्रत्यारोपण किया जाता है। लायन नकुल पटेल ने कहा कि मोतियाबिंद के मरीजों को ऑपरेशन के लिए चोइथराम नेत्र चिकित्सालय इंदौर भेजा गया है। इन 30 मरीजों को निःशुल्क लैंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। साथ ही नेत्र शिविर मे आए सभी मरीजों और उनके साथ आए व्यक्ति को क्लब द्वारा भोजन कराया गया। लायन सचिन शर्मा ने शिविर में उपस्थित हो कर कहा कि सभी मरीजों को अस्पताल की तरफ से दवाईयांए चश्मे और चाय नाश्ता तथा भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। आगामी शिविर दिनांक 21 अगस्त को जिला अस्पताल बड़वानी में होगा । लायन के एस मुजाल्दा ने जिला अस्पताल स्टॉफ तथा चोइथराम नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया।

संभागायुक्त ने किया कलेक्टर न्यायालय सहित अन्य न्यायालयों का निरीक्षण

माही की गूंज, बड़वानी।

संभागायुक्त दीपकसिंह बुधवार को बड़वानी जिले के भ्रमण पर आये। इस दौरान उन्होने सर्वप्रथम कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में स्थित कलेक्टर न्यायालयए अपर कलेक्टर न्यायालयए एसडीएम बड़वानी न्यायालय तथा तहसील बड़वानी के न्यायालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त न्यायालयों में संधारित की जाने वाली पंजियों एवं रिकार्ड का निरीक्षण करते हुए यह जाना कि न्यायालय में प्रतिमाह कितने प्रकरण दर्ज होते हैए तथा वे किस प्रवृत्ति के होते है। इस दौरान उन्होने न्यायालय में कार्यरत कर्मियों को निर्देशित किया कि राजस्व न्यायालय का रिकार्ड अत्यंत महत्वपूर्ण होता हैए अतः उसका बेहतर ढंग से संधारण किया जाना चाहिए। ताकि भविष्य में किसी प्रकरण में जानकारी मांगी जाने पर आसानी से दी जा सके। निरीक्षण के दौरान उन्होने एसडीएम बड़वानी एवं तहसीलदार बड़वानी को निर्देशित किया कि भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों में सुनवाई के लिए एक बार मौके पर ही जाकर स्थिति का भी निरीक्षण किया जाये। उसके बाद दोनों पक्षों को सुनकर उसका निर्णय दिया जाये। रिकार्ड रूम का किया निरीक्षण संभागायुक्त ने कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में स्थित जिला स्तरीय राजस्व रिकार्ड रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होने पुराना रिकार्ड सुरक्षित एवं बेहतर ढंग से रखा हुआ पाये जाने पर कलेक्टर डॉण् फटिंग से कहा कि राजस्व रिकार्ड रूम में रखा हुआ दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण होकर भविष्य के लिए उपयोगी होता है। संभागायुक्त के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉण् राहुल फटिंगए अपर कलेक्टर केके मालवीयए एसडीएम बड़वानी भूपेन्द्र रावतए तहसीलदार बड़वानी जगदीश कुमार वर्मा उपस्थित थे।

जिला चिकित्सालय में स्तनपान सप्ताह का हुआ समापन

माही की गूंज, खंडवा। श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय सह नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खंडवा में सिविल सर्जन डॉण् संजीव दीक्षित के मार्गदर्शन में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत सप्ताह भर अलग.अलग गतिविधियाँ की जाकर जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रसव पश्चात देखभाल कक्ष में शिशु रोग विभाग द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के समापन के अवसर पर पोस्टर प्रतियोगिता एवं नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें मेडिकल कॉलेज की छात्राओं द्वारा पोस्टर बनाकर महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉण् कृष्णा वास्केल एवं डॉण् गरिमा अग्रवालए डॉण् आयुषी एवं डॉण् अनन्या ने नाटक के माध्यम से महिलाओं को स्तनपान के लाभ बताए गए ताकि बच्चा कुपोषित ना हो एवं मां का स्वास्थ्य अच्छा रहे।

महिलाओं को लैंगिक अपराध की दी जानकारी

माही की गूंज, खंडवा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी विक्रांत दामले के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन खंडवा के वन स्टॉप सेंटर प्रभारी प्रशासक शीला सांवरे ने 100 दिवसीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत 6 अगस्त को ष्लैंगिक संवेदनशीलता सप्ताहष्् सह विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत जिला चिकित्सालय लेडी बटलर में महिलाओं को बताया गया कि 6 माह तक बच्चों को सिर्फ स्तनपान ही कराये इसके अलावा ऊपरी तरल पदार्थ कुछ न दें बच्चे के लिए माँ का पहला व पीला गाढ़ा दूध अमृत समान होता है। 7 अगस्त को महिलाओ को ष्लैंगिक संवेदनशीलता क्या होती है इस पर चर्चा हुई एवं महिलाओं से संबंधित नवीन कानूनों की जानकारी दी गई महिला सशक्तिकरण विषय पर चर्चा की गई और साथ ही डेस्क 112ए वन स्टॉप सेंटरए घरेलू हिंसाए छेड़.छाड़ए आदि सभी पर जागरूक किया गया।

आईटीआई विशिष्ट प्लेसमेंट ड्राईव में हुआ 213 उम्मीदवारों का चयन

माही की गूंज, खंडवा।

कौशल विकास संचालनालयए मध्यप्रदेश के निर्देशों के परिपालन में एवं इन्दौर क्षेत्र के संयुक्त संचालकए श्री एमण्जीण् तिवारी तथा जोनल टीपीओ श्रीमती मीना लोहिया के मार्गदर्शन में आईटीआई खण्डवा जिला नोडल टीपीओ आरण्केण् चौरे द्वारा 5 एवं 6 अगस्त को शासकीय आईटीआई खण्डवाए मूंदी एवं खेडी में प्लेसमेंट ड्राईव का आयोजन किया। दो दिवसीय इस प्लेसमेंट ड्राईव में 5 अगस्त को शासकीय आईटीआई खण्डवा में प्रतिष्ठित कंपनी आयशरए देवास ने तथा शासकीय आईटीआई मूंदी व खेडी में कंपनी मारुति सुजुकी और 6 अगस्त को शासकीय आईटीआई खण्डवा में कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा योग्य उम्मीदवारों का चयन किया। दो दिवसीय इस प्लेसमेंट ड्राईव में खण्डवा जिले के साथ.साथ ग्वालियरए सीहोरए उज्जैनए इन्दौरए मंदसौरए हरदाए बैतूलए खरगोन एवं बुरहानपुर जिले के लगभग 250 से अधिक अभ्यार्थियों ने भाग लिया जिसमें कंपनी आयशरए देवास द्वारा साक्षात्कार उपरांत 85 उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन तथा सुजुकी मोटर्स द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उपरांत 128 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। सुजुकी मोटर्स के द्वारा अंतिम चयनित प्रतिभागियों को कंपनी प्रतिनिधियोंए नोडल प्राचार्य श्री जीण्पीण् तिवारी एवं नोडल टीपीओ आरण्केण् चौरे द्वारा ऑफर लेटर प्रदान किये गये।

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नोडल प्राचार्य द्वारा बताया गया कि चयनित किये गये प्रतिभागियों को कंपनियों द्वारा योग्यतानुसार 11 हजार से 24 हजार पांच सौ पचास ;सीटीसीद्ध वेतन एवं अन्य सुविधाएं भोजन व्यवस्थाए मेडिक्लेम पॉलिसीए परिवहन सुविधा आदि दी जायेगी। संस्था प्राचार्य श्री जीण्पीण् तिवारी द्वारा चयनित सभी उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। संस्था के समस्त स्टॉफ ने प्लेसमेंट ड्राईव में सहयोग प्रदान किया।

सरकारी दुकानों पर एक्सपायर डेट की जहरीली शराब परोसी जा रही- पटेल

माही की गूंज, अलीराजपुर।

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल ने बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता मे बताया कि जिले में अवैध शराब का कारोबार, भंडारण ओर एक्सपायर डेट की जहरीली शराब सरकारी दुकानों मे धड़ल्ले से परोसी जा रही है। शराब ठेकेदार लोगो की जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी ओर विरोधस्वरूप सड़कों पर उतरकर करेंगी। श्री पटेल ने बताया कि हमको ज्ञात हुआ है कि शराब ठेकेदार द्वारा अवैध शराब का भंडारण जिलेभर में किया हुआ है, बिना रॉयल्टी के अवैध शराब सीमावर्ती राज्यों में परिवहन की जा रही है, उन्होंने बताया कि जिले में जितनी भी सरकारी दुकान शराब की है वहां पर एक्सपायर डेट की जहरीली शराब परोसी जा रही है, साथ ही अमानक स्तर की शराब बेचीं जा रही है। जैसे ही हमको सूचना मिली मे खुद शराब की सरकारी दुकान पर गया ओर वहां देखा कि दुकानदार द्वारा एक्सपायर डेट की जहरीली बियर ग्राहकों को दी जा रही थी। वही से हमने पुलिस ओर आबकारी विभाग को इसकी सूचना देकर अवगत कराया। पटेल ने जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों से माँग की है कि जिले में जितनी भी शराब की सरकारी दुकानें हैं, उनके गोडाउन की जांच ओर दुकानों से बिकने वाली शराब की एक्सपायर डेट की जाँच की जाए।

डिग्रीधारी चोरों ने महज 90 सेकेंड में उड़ाए एटीएम से 23 लाख, ना काटा ना ही तोड़ा

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले में पढ़े-लिखे डिग्रीधारी चोर ने बैंक ऑफ़ इंडिया की एटीएम मशीन से 23 लाख रुपये उड़ा दिए। चोरों ने शोल्डर शर्फिंग के जरिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर महज 90 सेकेंड में बिना तोड़-फोड़ के लाखों की लूट को अंजाम दिया। यह घटना खाचरोद थाने से महज 500 मीटर दूर घटी। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्त में लेकर लूटी हुई रकम बरामद कर ली है। यह घटना उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील की है।

सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 29 जुलाई की रात हेलमेट लगाए और रेनकोट पहने दो युवक बाइक से बैंक की गैलरी पहुंचे। एक युवक ने सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे करने के बाद एटीएम खोलकर मशीन से छेड़छाड़ की और दूसरा युवक बाहर खड़ा रहा। कुछ देर बाद दोनों युवकों को काले रंग का बैग ले जाते हुए देखा गया।

बैंक की ओर से शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की। जिस प्रकार से एटीएम में चोरी हुई थी उसे पुलिस को शंका हुई की आरोपी एटीएम मशीन खोलने में माहिर हैं या उसके पासवर्ड को जानते हैं। बाद में छानबीन में पता चला कि चोरी का मास्टरमाइंड आउटसोर्स मेंटेनेंस कर्मचारी है। इसके बाद पुलिस ने धरपकड़ तेज की तो एक युवक हत्थे चढ़ा।

शोल्डर सर्फिंग से महज 90 सेकंड में चुराए लाखों रुपए

पता चला कि ग्राम बरोदिया का रहने वाला आउटसोर्स टेक्नीशियन ऋतुराज 26 जुलाई को कंपनी की ओर से मेंटेनेंस के लिए आया था। पुलिस ने ऋतुराज को दबोचा तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मेंटेनेंस के दौरान उसने बैंक कर्मी के पीछे खड़े होकर पासवर्ड देखकर नोट कर लिया था। इस तरह उसने पासवर्ड की मदद से शोल्डर सर्फिंग के जरिए मात्र 90 सेकंड में लाखों रुपए चुरा लिए।

क्या होती है शोल्डर शर्फिंग

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शोल्डर सर्फिंग का मतलब होता है कि चोरी छुपे किसी के बगल से अथवा किसी जानकारी से एटीएम मशीन या किसी और पासवर्ड को देखना और उसे चुराना होता है इस प्रकार की चोरी प्रदेश में पहली बताई जा रही है इसके पहले एटीएम डिपॉजिट मशीन से उसे तोड़कर नष्ट कर या जलाकर चोरी की जाती थी।

बैंक की लापरवाही

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि इसमें बैंक की लापरवाही भी सामने आई है। 29 तारीख को जब एटीएम कैमरा से छेड़छाड़ होने के बाद भी बैंक के अधिकारी नहीं समझ पाए। हालांकि उन्होंने बताया कि एटीएम में काम करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है इसलिए इस चोरी का पता जब चला जब कर्मचारी बैंक में रुपए जमा करने गए। फिलहाल दोनो युवकों को गिरफ्तार करके चोरी की रकम बरामद कर ली है।

हाट बाजार में निकाली स्वच्छता जागरूकता रैली

माही की गूंज, बरझर।

बुधवार हाट बाजार के दिन ग्राम पंचायत बरझर में जलवायु अनुकुलता एवं स्टाप डायरिया अभियान के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला स्वच्छ भारत मिशन, अलिराजपुर के सामूहिक प्रयास से निकाली गई। इस रेली का मुख्य उद्देश्य पंचायत एवं पंचायत के आस-पास के गांव से अधिक लोगों को गीला एवं सूखा कचरा प्रबंधन, डायरिया से बचाव, घर के किचन से निकलने वाले पानी का प्रबंध, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जागरुकता फैलाना था। इस रैली में हाई सेकंडरी स्कूल, कन्या हाई स्कूल, माध्यमिक शाला बरझर के स्कूली छात्र छात्राए स्वच्छता के नारे लगाते हुए कदम ताल चल रहें थे साथ में क्षेत्र की आगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पंच-सरपंच जन प्रतिनिधी, सहित ग्रामवासीयों विशेष रूप से जागरूकता रैली में शामिल हुए।

रैली में सीईओ, बीईओ व बीआरसी के नेतृत्व में जागरुकता रैली को सफल बनाने ग्राम संरपच हिमसिंग बारिया, प्राचार्य केशव सिंह सोलंकी, कन्या स्कूल प्राचार्य शैलेन्द्र शर्मा, सचिव शंकर, ब्लाक समन्वय गमसिंग मेड़ा, शिक्षक रामसिंग राठोड़, शिक्षक सुरेश शाहू, फिरोज खान, प्रताप, स्वेता राठोड, कान्ति सिसोदिया, पुलिस विभाग के कर्मचारी सहित शिक्षा विभाग का सराहनीय सहयोग रहा।

लाडली बहनों को खाते में कब 'शगुन' देगी एमपी सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी रक्षाबंधन पर 'लाडली बहनाओं' को शगुन देने के लिए अपना दिल और सरकार का खजाना खोल दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए रक्षाबंधन समारोह में 'लाडली बहना' योजना की सभी लाभार्थियों को 250 रुपये शगुन के साथ कुल 1500 रुपये देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी को राज्यभर में धूमधाम से मनाएगी।

रक्षाबंधन की तैयारियों पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, ÷इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को है, इसलिए हमने तय किया है कि इसे 10 अगस्त से सभी पंचायतों, वार्डों और जिलों में 25,000 स्थानों पर मनाया जाएगा, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक कदम है। इस अवसर पर, मध्य प्रदेश सरकार 'लाडली बहना' योजना की लाभार्थियों के खातों में 1250 रुपये के साथ अतिरिक्त 250 रुपये शगुन के तौर पर ट्रांसफर करेगी।÷

सीएम यादव भोपाल स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। इसके अलावा सीएम यादव ने प्रदेश के 55 जिलों में ÷पुलिस बैंड÷ के गठन की भी घोषणा की, जो स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग लेंगे।

पुलिस बैंड के गठन के बारे में जानकारी देते हुए मोहन यादव ने कहा कि 15 अगस्त तक हर जिले में पुलिस बैंड तैयार हो जाएंगे। पुलिस बैंड 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड में भाग लेंगे। 12, 13 और 14 को जिला स्तर पर पुलिस बैंड के साथ शहीद स्मारक पर ध्वजारोहण किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सीएम यादव ने कहा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही त्योहारों का महत्व अन्य सभी त्योहारों से कहीं अधिक है। हाथ में तिरंगा लेकर हम समाज को जागृत करेंगे।

सीएम यादव ने यह भी घोषणा की कि राज्य आधिकारिक तौर पर पूरे राज्य में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मथुरा और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी तरह मध्य प्रदेश भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थान हैं, जो श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और इसलिए हमने राज्य में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का फैसला किया है।

बांग्लादेश संकट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र मनाने का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के लोकतंत्रों की स्थिति को देखते हैं, चाहे वे पहले स्वतंत्र हुए हों या बाद में। बांग्लादेश में क्या हुआ और पाकिस्तान में पहले क्या हुआ। इन देशों में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन देशों में राष्ट्रवादियों और राष्ट्रीय दलों की कमी थी, जो नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना जगा सकें और समाज में जागरूकता पैदा कर सकें।

उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हमारे पास पीएम मोदी हैं जिन्होंने 2014 में बहुमत के साथ चुनाव जीता और 2024 में भी तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। नेहरू के कार्यकाल में लोकतंत्र अपने शुरुआती दौर में था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लोकतंत्र स्थिर है। नतीजतन, हमें समाज के साथ खड़ा होना चाहिए और मध्य प्रदेश को इसमें प्रभावी रूप से योगदान देना चाहिए क्योंकि भाजपा ने मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है।

श्रावण मास के तृतीय सोमवार को आम्बुआ शिवालय में महाआरती संपन्न

माही की गूंज, आम्बुआ।

यह समय पवित्र श्रावण मास का होकर प्रति दिन शिवालयों में पूजा अर्चना का चल रहा है। सुबह से लेकर रात तक यह क्रम जारी रह रहा है। इसी कड़ी में श्रावण मास के तृतीय सोमवार को आम्बुआ के प्राचीन शिवालय में भोलेबाबा का आकर्षक श्रृंगार किया जाकर पुजारी श्री शंकरलाल पारिख द्वारा महाआरती की गई, इस अवसर पर बाल शिव भक्त मंडल एवं महिला मंडल द्वारा सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। उपरांत महाप्रसादी का वितरण किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी ने क्लिनिक का किया निरीक्षण

माही की गूंज, अलीराजपुर। कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए है कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाए ताकि लोगों स्वास्थ्य लाभ ले सके और जिले में कही भी अवैध चिकित्सा का संचालन न हो। इसी निर्देश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर तपीस पांडे द्वारा अलीराजपुर के कुम्हारवाड़ा स्थित क्लीनिक की जांच की। इस दौरान संबंधित द्वारा क्लीनिक संचालन संबंधी कोई भी दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं कराने पर क्लीनिक के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सा अधिकारी को संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। उन्होने बताया कि इस तरह की कार्यवाही आगामी दिवसों में भी जारी रहेगी।

ग्राम पंचायत पस्टार के उकला फलिए व झरी फलिए के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में दिया आवेदन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

ग्राम पंचायत पस्टार में पस्टार से कुहा तक करीब 5 किलोमीटर का रोड है, जो कि बरसों से दुर्गम व खस्ता हालत में है। रोड कच्चा होने से बारिश में भारी कीचड़ हो जाता है और आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही इमरजेन्सी एम्बुलेंस आदि नही निकल पाता है, इस कारण से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों एवं गर्भवती बहाने एवं माताओं को एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं मिल पाती हैं रोड के खस्ता हालत के कारण अस्पताल नही पहुच पाने से मृत्यु तक हो जाती है।इस विषय में बरसों से सरपंच एवं अन्य वरिष्ठ जिम्मेदार अधिकारियों को निराकरण हेतु निवेदन किया है। समस्या जस की तस हैं और रोड़ नहीं बन पाया है। ग्रामीण जिला अध्यक्ष अरविंद कनेश एवं सक्रिय जयस कार्यकर्ता देवा कनेश विक्रम बामनिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेड पहुच कर जनसुनवाई में आवेदन देकर इस लगभग 5 किमी मार्ग का डामरीकरण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण करवाये जाने की मांग की गई है।

उक्त मार्ग का निर्माण कर डामरीकरन किया जाता है तो ग्राम की आवागमन संबंधी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकता एवं ग्रामीणों को शासन कई सुविधाओं का लाभ मिल सकता हैं। इस दौरान देवा कनेश विक्रम बामनिया प्रदीप, नरसिंह, गमिर, वेरसिंह मंजु डुंगेरसिंह, भायत्ता, दसम, भुवान, प्रताप, भुरसिंह, इन्दरसिंह, टेमता, किदान, भुरला, कमिक्ष, बबलु, दिपला, पानसिंह, सरदार केचरसिंह, नरसिंह, किशन आदि ग्रामीण उपस्थित थे।

दशा माताजी की मूर्ति स्थापित कर दस दिवसीय आयोजन प्रारंभ

माही की गूंज, आम्बुआ।

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण मास की अमावस्या को दशा माताजी की मूर्ति स्थापित की जा कर दस दिवसीय आयोजन प्रारंभ किया गया, स्थापना पूर्व माताजी की मूर्ति का चल समारोह निकाला गया, आम्बुआ में तीन स्थानों पर, आयोजन किया जा रहा है। अपने परिवार घर तथा क्षेत्र की दशा सुधारने हेतु क्षेत्र में सावन मास की अमावस्या के दिन दशा माताजी की मूर्ति स्थापित की गई। स्थापना पूर्व माताजी की मूर्ति का चल समारोह ढोल-ढमाके के साथ निकाला गया, तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ स्थापना की गई। दस दिनो तक पूजा अर्चना तथा आरती के साथ माताजी के भजन गरबा आदि के आयोजन भी किए जाएंगे। दस दिवसीय पूजा अर्चना उपरान्त 11वें दिवस माताजी की मूर्ति का विसर्जन जलाशयों में किया जायेगा,इस बार आम्बुआ में कुम्हार मोहल्ला, मेलडी माताजी मंदिर तथा इंदिरा आवास बीजासन माता मंदिर प्रांगण में मूर्ति स्थापित की गई है।

विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी अंतिम दौर में, 500 युवा वालेंटियर की निगरानी में होगा आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएनओ) द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त नजदीक है जैसे जैसे समय आ रहा है तैयारी बढ़ती और उत्साह बढ़ता जा रहा है, तैयारीया अंतिम दौर मे चल रही है।आदिवासी समाज के युवाओं मे ड्रेस टीशर्ट बनाने का कार्य जारी है तो पारम्परिक वाध्य यन्त्र तैयार किये जा रहे है। जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय आयोजन कि तैयारी को लेकर आयोजक कमिटी ने निरिक्षण कर व्यवस्था जायजा लिया और समुचित टेंट,पानी कि व्यवस्था हेतु चिन्ह अंकित कर योजना को अंतिम रूपये दिया।

ज्ञात रहे कि, ईस वर्ष भी जिला स्तरीय आयोजन जिला मुख्यालय अलीराजपुर कॉलेज ग्राउंड पर ही होगा।जहां जिले भर के विभिन्न समाज के गणमान्य नागरिक जिले के जनप्रतिनिधि और आम जन हजारों कि संख्या मे शामिल होंगे और समाज के हक अधिकारों को लेकर वैचारिक रूप से उदबोधन होंगे। आदिवासी संस्कृति सभ्यता परम्परा जल, जंगल, जमीन को बचाने हेतु संकल्प लेकर आदिवासी समाज के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करते है, सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुति हेतु सोपटे वाध्य यन्त्र और नृत्य हेतु विशेष दल आएंगे। इस वर्ष स्थानीय जिले के तीनो जनप्रतिनिधि सांसद अनीता चौहान, मध्यप्रदेश शासन के केबिनेट मंत्री अनुसूचित जाती कल्याण विभाग नागरसिंह चौहान और जोबट विधायक सेना पटेल जी का मंच से स्वागत सम्मान सहित जिले भर कि अलग अलग प्रतिभाओ का सम्मान किया जायेगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु 500 युवा वालेंटियर को निगरानी हेतु तैयार किया गया है जो कार्यक्रम स्थल से लेकर सांस्कृतिक रैली मे अपनी निगरानी बनाये रखेगी और जगह जगह वीडियो ग्राफी के साथ ही शरारती तत्वों पर भी निगरानी रखेंगे।

शासन के आदेश प्रशासन के लिए दुधारू गाय...

माही की गूंज। संजय भटेवरा

झाबुआ। लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन और प्रशासन दो महत्वपूर्ण हिस्से है। शासन की योजनाओं को मूर्त रूप देने का जिम्मा प्रशासन का रहता है। कई बार शासन कुछ नियम प्रशासन के लिए दुधारू गाय बन जाते हैं और शासन के नियमों की आड़ में प्रशासन के नुमाईंदे जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। कुछ ऐसा ही एक आदेश शासन द्वारा जारी किया है जिसमें शासन ने बिना डिग्रीधारी, झोलाछाप फर्जी डॉक्टरों को प्रदेश में कहीं भी इलाज करने हेतु बेन किया है और बीमार व्यक्ति का इलाज डिग्रीधारी डॉक्टर अथवा सरकारी अस्पतालों में करवाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के हस्ताक्षर से जिले के समस्त कलेक्टर और समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से पत्र क्रमांक, विनियमन, 2024, 248 भोपाल 25 जुलाई 2024 को एक पत्र जारी हुआ है। जिसमें गैर मान्यता धारी व्यक्तियों, झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा प्रदायित चिकित्सकीय व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु निम्न निर्देश दिए गए हैं।

(1) प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों, झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा अनैतिक चिकित्सीय व्यवसाय को नियंत्रित करने हेतु समस्त जिलों में अमानक क्लीनिक व चिकित्सकीय स्थापनाओ को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।

(2)जन समुदाय में ऐसे अपात्र व्यक्तियों से उपचार प्राप्त करने पर संभावित दुष्परिणामों के संबंध में जागरूकता लाई जाए एवं शासन द्वारा ग्रामीण स्तर तक उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित की जाए।

मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधियम 1973 की धार 3 के अंतर्गत बिना उचित पंजीयन के ऐसे अमानक चिकित्सकिय स्थापनाओं का संचालन अवैध है एवं अधिनियम के उल्लंघन पर विधिक कार्यवाही उपरांत दंडनीय अपराध है।

इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण अधिनियम 1973, यथा संशोधित अधिनियम 1975 एवं संशोधन अधिनियम 2006 की धारा 7-ग अनुसार 'डॉक्टर' शब्द अपने नाम के आगे वही व्यक्ति लिख सकता है जो कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सिकिय अर्हता धारित करता हो और जो तत्समय प्रवत विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड या परिषद या किसी अन्य संस्था में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है। अन्य कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है। इस अधिनियम की धारा 7-ग के उल्लंघन में 3 वर्ष तक का कारावास व 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के उक्त आदेश को भी झाबुआ जिला प्रशासन ने बना दिया अपना कमाई का जरिया।

इस पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध चिकित्सकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही हेतु अग्रेषित करें। जिसके बाद झाबुआ जिले में इन अवैध चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु दल बनाकर छापामारी की जा रही है। खवासा क्षेत्र में भी विगत दिनों टीम पहुंची थी लेकिन खाली हाथ लौटी लगभग सभी अवैध क्लिनिक बंद पाए गए।

अब सवाल यह उठता है कि, इन अवैध क्लिनिकों को छापामारी की सूचना किसने दी...? या तो प्रशासन की टीम ने ही केवल अपने कर्तव्यों की इतिश्री मात्र कागजी खाना पूर्ति करके कर ली। या फिर पर्दे के पीछे से लेनदेन की बातें तय होने के बाद खुद प्रशासन ने उन्हें सूचना देकर आम जनता के सामने झूठी वाह-वाही लूटने का प्रयास किया। या फिर इन अवैध चिकित्सकों का नेटवर्क बहुत मजबूत है जिसे उन्हें छापेमारी के पूर्व में ही सूचना मिल जाती है। बहरहाल जो भी कुछ हुआ उसके केवल और केवल प्रशासन की विफलता ही नजर आ रही है।

पूरे जिले में फैले हैं झोलाछाप

एक तरफ देश के स्वास्थ्य मंत्री सदन में जानकारी देते हैं कि, पूरे देश में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है और देश में जनसंख्या और डॉक्टरों का अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यु एच ओ) के अनुसार तय मानकों से अधिक है। वहीं झाबुआ जिले के संदर्भ में देखे तो यहां गांव और फलियो-फलियो तक अवैध झोलाछाप डॉक्टर मौजूद है। जिन्हें स्थानीय भाषा में बंगाली डॉक्टर कहा जाता है इन फर्जी डॉक्टरों में कई बांग्लादेशी भी है जो चोर रास्ते से भारत आकर झाबुआ जिले तक आ गए है जिसका खुलासा पुर्व में मय प्रमाण के माही की गूंज कर चुका है। पूरे जिले में फैले इन तथा कथित डॉक्टर का मजबूत संगठन बना हुआ है और प्रशासन व शासन तक इनकी मजबूत पकड़ है। यही कारण है कि, जितनी भी छापामारी हो जाए और जितने ही आदेश निकल जाए कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है मुख्यमंत्री के आदेश के साथ यह एक बार फिर साबित हो चुका है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासन ने एक पत्र जारी किया और वह पत्र प्रशासन के नुमाईदे के लिए दुधारू गाय ही साबित हुआ। दिखाने को तो जिले में कार्यवाही की गई लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ और जो हुआ वो आम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया।

दवाखाने के साथ मेडिकल स्टोर भी

इन तथाकथित डॉक्टर ने अवैध दवाखाने के साथ ही मेडिकल स्टोर का भी संचालन करते हैं और मरीजों को बाटल लगाने के साथ ही सस्ती व जेनरिक दवाईयां देकर मोटी रकम वसूल करते हैं। जबकि मेडिकल व्यवसाय के लिए भी फार्मेसी की डिग्री होना आवश्यक है और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए भी शासन ने कुछ गाइड लाइन तय कर रखी है लेकिन इन तथाकथित बंगाली डॉक्टरों ने इन नियमों की भी धज्जियां उड़ा रखी है। जो किसी और के नाम पर मेडिकल खोलकर उसकी आड़ में फर्जी क्लीनिक चला रहे है।

किसी और के नाम से मेडिकल लाईसन्स लेकर इस तरह से जिले में चला रहे फर्जी बंगाली व बांग्लादेशी अपना अवैध क्लीनिक।

खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया डॉक्टरों की दल-बदल की प्रयोगशाला

ग्रामीणों को नहीं मिल रहा शासकीय स्वास्थ्य सम्बन्धित कोई लाभ

बिना डॉक्टर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ओपीड़ी पर्ची पर उपचार।

माही की गूंज, खवासा।

जहा ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रो का सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण ग्रामीणों को मजबूरन अवैध चिकित्सकों के यहां इलाज करने को विवश होना पड़ रहा है। वही जिले के जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण अंचलों में बने अस्पतालों में डॉक्टर नदारत दिखाई देते हैं। थांदला अंतर्गत खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करे तो इस प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र के अधिन करिब 20 पंचायतो के 50 से अधिक गाव आते है। उसके बावजुद स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी 50 हजार से अधिक क्षेत्र के सहवासियो के स्वास्थ्य के साथ अक्सर खिलवाड़ करते ही नजर आते रहै है। कई समय तक यह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डॉक्टर विहिन ही रहा है। वही जिस-जिस डॉक्टर की पदस्थापना की गई वह भी अस्थाई ही रहे है। खवासा में पदस्थ किये जाने वाले डॉक्टर को विभाग के आला अधिकारी अपनी मर्जी के साथ कभी भी कही और पदस्थ या अटेच कर दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियो के अपने मनमाने प्रयोगो के साथ खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को डॉक्टर दल-बदल की एक प्रयोगशाला बनाकर क्षेत्र के ग्रामिणो के स्वास्थ्य के साथ अक्सर खिलवाड़ ही करते रहै है।

पानी में मच्छरो के बिच बिना देख रेख के जर्जर अवस्था में एंबुलेंस।

वर्तमान स्थिति की बात करे तो बारिश के मोसम के चलते कई बिमारियो का प्रकोप रहता है। ऐसे में भी वर्तमान में भी विभाग के आला अधिकारियो के प्रयोग का दंश ग्रामीण झेलने को मजबुर है। वर्तमान मे भी सामने आया की यहा डॉक्टर राकेश निनामा पदस्थ है लेकिन उनकी ड्यूटी अमरनाथ तरफ लगा दी गई है। वही खवासा मे कोई भी प्रभारी चिकित्सक भी नहीं है। यहां कंपाउंडर, स्टॉफनर्स, लैब टेक्नीशियन सभी है लेकिन सिर्फ पर्ची के आधार पर ग्रामीणों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर विहिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने के चलते खवासा व आसपास क्षेत्र की पचास हजार की आबादी मजबूरन अवैध चिकित्सकों के यहां इलाज करने को विवश होना पड़ रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण बारिश के दिनों में भी खवासा मे डाक्टर उपस्थित नहीं है। जबकि इन दिनों बारिश का मोसम होने के चलते वायरल फीवर के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बना हुआ है। हर दिन ओपीडी में अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां उनकी देखरेख करने वाले डॉक्टर ही उपस्थित नहीं है।

जानकारी के अनुसार खवासा में पदस्थ डॉक्टर राकेश निनामा की अमरनाथ तरफ ड्यूटी लगा रखी है जिसके बाद से खवासा में कोई भी प्रभारी चिकित्सक नहीं है। जिससे आने वाले ओपीडी में मरीजों को सिर्फ पर्ची में दवाई लिखकर स्टाफ नर्स द्वारा काउंटर पर दवाई दि जा रही है। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार, किसी डॉक्टर को यहा का प्रभारी चिकित्सक बना रखा है लेकिन वह आना उचित ही नहीं समझ रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बीमारी का निज़ाद शासकिय उपचार के साथ नहीं मिल पा रहा है। जिससे मजबूरी वश इनको खवासा क्षेत्र में अवैध चिकित्सक के यहां इलाज करने को मजबूर होना पड़ रहा है या दाहोद-रतलाम जाना पड़ रहा है।

एंबुलेंस भी जर्जर अवस्था में

बारिश के दिनों में मौसमी बीमारियों के साथ ही उल्टी, दस्त आदि होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छता रखने के उपाय बताए जा रहे हैं। तो साथ ही मच्छर आसपास न पनपने देवे आदि जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई जाती है। लेकिन खवासा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में पानी ही पानी भरा हुआ है जो एंबुलेंस के समीप भरा हुआ है। जब भी यहां बारिश होती है तो गड्ढे का रूप ले लेता है पानी की निकासी नहीं होने के कारण बिच सेंटर पर गेट के समीप एंबुलेंस जहां पड़ी है वहां पानी भरा हुआ रहता है। इससे मच्छर पनपने व मोसमी बीमारियों का प्रकोप ज्यादा रहने का खतरा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां एक एंबुलेंस पड़ी हुई है उसकी भी देखरेख नहीं होने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है।

जितना खतरा बेसमेंटों से नही, उससे कई अधिक खतरा शहर मे खड़े जर्जर भवनो से

प्रशासन व नगरपालिका : बेसमेंटों पर कार्रवाई के कागजी घोड़े दौड़ाना बंद करे असल समस्या पर दें ध्यान

कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारों के ढकोसले झाबुआ में भी सागर जिले के शाहपुर जैसी घटना को दोहरा जाए

माही की गूंज, झाबुआ।

पिछले दिनों दिल्ली में एक बेसमेंट में पानी भरने से तीन मौतें हो गई थी। असर ऐसा हुआ कि, पश्चिमी मध्यप्रदेश के ठेठ आदिवासी अंचल में भी इसका असर देखने को मिला। दिल्ली में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन और नगरपालिका ने यहां भी खोज बीन शुरू की और नगरीय निकायों में बने निजी बेसमेंटों पर कार्रवाई के कागजी घोड़े दौड़ाए। हालांकि जिले में कहीं भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां बेसमेंट में किसी तरह के शैक्षणिक संस्थानों का संचालन हो रहा हो, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन, नगरपालिका व नगरपरिषदों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। कई जगह बेसमेंटों में बनी दुकानों व गोदामों पर कार्रवाई की गई। हालांकि इन तमाम जगहों में कहीं भी यह स्थिति कतई नहीं थी कि, बेसमेंट में कहीं से पानी भर रहा हो। मगर बावजूद इसके प्रशासन व नगरपालिका -परिषदो ने बेसमेंटों पर पंचनामें बनाए।

विडम्बना यह कि, इनमें से कुछ के पास बेसमेंट बनाने की परमीशन तक नहीं थी। जिनके पास परमीशन थी वह भी पार्किंग या गोडाउन बनाने की, व्यवसाय की नहीं। बावजूद इस तरह के निर्माण व बेसमेंट बनाए गए। वैसे देखा जाए तो यह प्रशासन की ही गलती कही जाएगी। क्योंकि प्रशासन और नगरपालिकाएं इसको लेकर पहले ही एक बड़ी गलती कर चुके है। आखिर यह कैसे संभव है कि, जिले में इतनी संख्या में बेसमेंट बनाए गए और प्रशासन व नगरपालिकाओं को भनक तक नहीं लगी। या फिर इस तरह के निर्माण को टेबल के नीचे से खुद प्रशासन और नगरपालिकाओं ने ही परमीशन दी। अब कार्रवाई करके प्रशासन और नगरपालिकाएं खुद अपनी ही जांग उघाड़ रहे है।

नगरपालिका काम्प्लेक्स की दुकानों में बने बेसमेंट में बारिश के दौरान भर जाता है पानी

जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो प्रशासन की इस कार्रवाई की स्थिति ढाक के तीन पात जैसी ही नजर आएगी। क्योंकि जिन स्थानों पर जिला प्रशासन व नगरपालिकाओं ने कार्रवाई की है वह निर्माण लगभग नए ही है और मजबूत भी है। मगर इसके उलट जिला मुख्यालय पर नगरपालिका द्वारा बनाया गया एक ऐसा भी काम्प्लेक्स है जहां हर दुकान में बेसमेंट मौजूद है और उन बेसमेंटों में बारिश के दौरान पानी भी भर जाता है। नगरपालिका का यह काम्प्लेक्स लगभग 3-4 दशक से भी ज्यादा पुराना है। बावजूद इसके नगरपालिका ने ऐसी किसी भी जगह पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक सरअंजाम नहीं दी है। चाचा नेहरू बालोद्यान से लग कर मेन रोड पर बना नगरपालिका का यह काम्प्लेक्स हर बारिश में बेसमेंटों में पानी भर जाने का शिकार होता है। कई दुकानदार इस समस्या से वर्षों से दो-चार हो रहे है, लेकिन नगरपालिका है कि इस ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। इस काम्प्लेक्स में बनी लगभग हर दुकान में बेसमेंट मौजूद है। इनमें से कई दुकानें ऐसी है जिनके बेसमेंट में बारिश के दौरान पानी भर जाता है। बेसमेंट में पानी भरने से दुकानदार और दुकान में काम करने वाले हमेशा खतरे से खेलते दिखाई पड़ते है। बारिश के दिनों में काम्प्लेक्स के नीचे से गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो होता है और दुकानों के बेसमेंट में पानी भर जाता है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब शहर का छोटा तालाब ओवरफ्लो होता है। क्योंकि छोटे तालाब का ओवरफ्लो इसी नाले से होकर रामकुले नाले में मिलता है। इस काम्प्लेक्स के तमाम दुकानदारों की यह हमेशा की समस्या है। ऐसा भी नहीं है कि, इस समस्या को लेकर कभी दुकानदारों ने आवाज नही उठाई। मगर बावजूद इसके कभी भी नगरपालिका व प्रशासन दुकानदारों की इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दिए। इस बार भी थोड़ी ही बारिश के बाद चाचा नेहरू बालोद्यान जिसमें अब सब्जी मंडी लगती है, में पानी भर गया था जिसके चलते काम्प्लेक्स में बनी कई दुकानों के बेसमेंट में पानी का भराव हो गया था जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना था। इस काम्प्लेक्स की हर दुकान के बेसमेंट में दुकानदारों ने लाइट भी लगा रखी है मतलब इन बेसमेंटों में बिजली का प्रवाह बना रहता है। अगर भगवान न करे और इन दुकानों में बने बेसमेंटों में अगर पानी भरने के दौरान करंट फैल जाए तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

नजर अंदाज करना कहां तक उचित...?

बस स्टेंड पर वर्षों से जर्जर अवस्था में खड़ी यह धर्मशाला अगर बारिश के चलते गिरी तो जनहानी होना तय है।

नपा के इस काम्प्लेक्स की दुकानो के बेसमेंट में बारिश में भर जाता है पानी, मगर कोई कार्रवाई नही।

प्रशासन ने दिल्ली दुर्घटना के बाद उपर से मिले आदेशों पर इस तरह से कागजी घोड़े दौड़ाएं है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चूंकि जिस मकसद को लेकर कार्रवाई होना थी वह मकसद यहां बिल्कुल भी पूरा होता दिखाई नही पड़ रहा है। खुद अपने ही बनाए हुए काम्प्लेक्स के बेसमेंटों को नजर अंदाज करना कहां तक उचित है...? जबकि नगरपालिका द्वारा निर्मित यह काम्प्लेक्स अपनी उम्र पूरी कर चुका है...!

वर्षों से घनी आबादी के बीच खड़े जर्जर भवन

बावजूद इसके अगर प्रशासन ने शहरों में निजी बेसमेंटों पर इस तरह की कार्रवाई की है तो ठीक ही है। मगर इसके उलट जिले में कई भवन ऐसे है जो वर्षों से घनी आबादी के बीच जर्जर अवस्था में खड़े हुए है। अगर इनमें से इस वर्षाकाल में कोई भवन गिरता है तो जन हानी होना तय ही है। पिछले वर्ष बाबेल चौराहे पर बने एक पुराने और जर्जर भवन की छत बारिश से टूटकर गिर चुकी है। साल भर हो गया लेकिन अब तक नगरपालिका इस जर्जर भवन को जमीदोज नही कर पाई है। ऐसे कई उदाहरण जिला मुख्यालय पर मौजूद है जिनसे वर्षा काल में जनहानी होना संभावित है। शहर में बना नगरपालिका का एक और काम्प्लेक्स है जो अपनी जर्जर अवस्था पर आंसू बहा रहा है। शहर के मुख्य मार्ग पर बना नगरपालिका का रघुनंदनशरण काम्प्लेक्स बहुत ही दयनीय स्थिति में है। स्थिति इतनी गंभीर है कि, इस काम्प्लेक्स की छत से बारिश में प्लास्टर, पानी के साथ नीचे गिर रहा है मगर कोई सुध लेने वाला नहीं है। बावजुद दुकानदार लगातार इस जर्जर काम्प्लेक्स में अपनी दुकानें चला रहे है।

वर्षों से जर्जर स्थिति में धर्मशाला

बस स्टेंड पर बनी धर्मशाला भी नगरपालिका की ही है और वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। इस धर्मशाला का पूरा का पूरा भवन जर्जर है। पिछले वर्ष प्रशासन और नगरपालिका का अमला इसे खाली करवाने पहुंचा था। मगर एक साल बीत जाने के बाद भी इस जगह को ना तो खाली करवाया जा सका और ना ही इस जर्जर धर्मशाला को नगरपालिका अब तक जमीदोज कर पाई है।

यह भवन भी वर्षों से जर्जर अवस्था में

इसके अलावा भी शहर के बीचों-बीच ऐसे कई भवन है जो जर्जर अवस्था में होकर दुर्घटना को न्यौता देते दिखाई पड़ रहे है। आजाद चौक स्थित एक सरकारी बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में वर्षों से खड़ी है। विडम्बना यह कि, यहां अब भी आबकारी विभाग का कार्यालय संचालित हो रहा है। इसके अलावा चारभूजानाथ मंदिर चौराहे पर भी एक जर्जर भवन खड़ा है जो पिछले कुछ वर्षों में बारिश से लगातार गिरता जा रहा है। मगर इन भवनों पर नगरपालिका ने किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक नही की है। जब भी नगरपालिका में बैठे जिम्मदारों से इस पर सवाल किया जाता है, तब -तब वे सिर्फ नोटिस देने की ही बात करते है। इसके अलावा नगरपालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती।

खतरा बेसमेंटों से नहीं जर्जर भवनों से

अब सवाल यह कि, जितना खतरा नगरवासियों को नगर में बने बेसमेंटों से नहीं है, उससे कई गुना अधिक खतरा शहर में जहां-तहां खड़े जर्जर भवनों से है। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की जान चली गई थी। कहीं ऐसा ना हो की प्रशासन और नगरपालिका बेसमेंटों पर कार्रवाई के कागजी घोड़े दौड़ाते रहे और शहर में खड़े जर्जर भवन किसी गंभीर हादसे को न्यौता दे दे। यह बारिश का समय है और इस समय में अगर कोई जर्जर भवन गिरता है तो जनहानी होने का खतरा लगातार बना हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि जिम्मेदारों के ढकोसले झाबुआ में भी सागर जिले के शाहपुर जैसी घटना को दोहरा जाए...!

जर्जर अवस्था में पड़ा नपा का रघुनंदनशरण काम्प्लेक्स, छत से सरिये झांक रहे तो, शौचालय की स्थिति भी खंडहर।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422